

## वैदेशिक क्षेत्र: सतर्क और आशावान

भारत का विदेशी क्षेत्र प्रतिकूलताओं और अनिश्चितता से बार-बार प्रभावित हुआ है, जिससे वैश्विक पण्य वस्तुओं (कमोडिटी) की कीमतों में वृद्धि दिखाई दी, हालाँकि जो अब घट रही है; अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थितियों को कड़ा किया गया; वित्तीय बाजार में अस्थिरता बढ़ गयी; पूंजी प्रवाह का उत्क्रमण हुआ; मुद्रा मूल्यहास हुआ, और वैश्विक विकास व व्यापार को मंदी का सामना करना पड़ा। हालाँकि, यह मैक्रोइकॉनॉमिक फंडामेंटल और बफर स्टॉक की मजबूत स्थिति से इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम रहा है।

वित्त वर्ष 23 (दिसंबर 2022 तक) के दौरान भारत के निर्यात ने वित्त वर्ष 22 में निर्यात के रिकॉर्ड स्तर के बाद लचीलेपन का प्रदर्शन किया है। पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, जैविक और अकार्बनिक रसायन, दवाएं और फार्मास्यूटिकल्स प्रमुख निर्यात वस्तुओं में से थे। हालाँकि, वैश्विक व्यापार में मंदी की विशेषता वाली धीमी वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारतीय निर्यात में मंदी अपरिहार्य रही। मध्यम से दीर्घावधि दृष्टिकोण में, बाहरी क्षेत्र के लचीलेपन में सुधार लाने में निर्यात की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए, विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन उपायों पर विचार किया जा रहा है/उनको कार्यान्वित किया जा रहा है। ये उपाय उस अंतर्निहित तुलनात्मक लाभ का पोषण करेंगे जो भारतीय निर्यात में समाविष्ट रहेंगे। इसके साथ, जहाँ नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी (राष्ट्रीय संभार तंत्र नीति) आंतरिक लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करके भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए घरेलू बाधाओं को कम करेगी, वहीं नवीनतम मुक्त व्यापार समझौते, जैसे संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए हैं, रियायती टैरिफ दर देंगे और गैर-टैरिफ बाधाओं पर निर्यात के अवसर देकर विदेशी बाधाओं को समाप्त कर सकेंगे। इस प्रकार, संपूर्ण आर्थिक प्रणाली समय के साथ निर्यात-अनुकूल तरीके से विकसित होगी।

कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतों के अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों के पुनरूद्धार ने आयात में वृद्धि की है। पेट्रोलियम कच्चे और उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोयला और कोक ब्रिकेट आदि मशीनरी इलेक्ट्रिकल एवं गैर इलैक्ट्रिकल तथा स्वर्ण जैसी शीर्ष आयात वस्तुओं में शामिल थे। जहाँ वैश्विक पण्य मूल्य की स्थिति में निरंतर नरमी आयात को आगे बढ़ने में मदद करेगी, वहाँ गैर-स्वर्ण, गैर-तेल आयात में उल्लेखनीय कमी नहीं हो सकती है। इसके अलावा, भारतीय रुपये में अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्थापन को बढ़ावा देने के प्रयास चल रहे हैं। एक बार जब इन उपायों ने गति पकड़ ली, तो विदेशी मुद्रा पर निर्भरता कम होगी जो संभावित रूप से अर्थव्यवस्था को विदेशी आर्थिक परिवर्तनों के प्रति कम संवेदनशील बना देगी।

भुगतान संतुलन (BoP) को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दबावों का सामना किया। व्यापार की अदृश्य मद (सेवाएं, हस्तांतरण, और आय) पर अधिशेष द्वारा इसे मंद किए जाने के बावजूद, जहाँ तेल की कीमतों में तेज वृद्धि का प्रभाव चालू खाता घाटा (सीएडी) के बढ़ने में दिखाई दे रहा था वहीं अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा नीति को कड़ा करने और अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में बहिर्वाह हुआ। नतीजतन, पूंजी खाते का अधिशेष चालू खाते के घाटे से कम था, जिससे भुगतान संतुलन (BoP) के आधार पर विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई। हालाँकि, आगे चलकर, कच्चे तेल की कीमतों में अपेक्षित कमी, शुद्ध सेवाओं के निर्यात का लचीलापन और आवक धन-प्रेषण में वृद्धि के परिणामस्वरूप

वित्त वर्ष 23 के शेष के दौरान चालू खाता घाटा (CAD) कम होगा और इसके वहनीय सीमा के भीतर रहने की आशा है। वैश्विक विपरीत परिस्थितियों को कम करने के लिए भारत के विदेशी क्षेत्र के सुरक्षा उपाय (फोर्टिफाइड शॉक एब्जॉर्बर) विद्यमान हैं चाहे वह दुर्जेय विदेशी मुद्रा भंडार, स्थायी विदेशी ऋण संकेतक अथवा बाजार-निर्धारित विनिमय दर हो। जबकि दिसम्बर 2022 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार 562.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, (9.3 महीने के आयात के बराबर) और सितंबर 2022 के अंत तक सकल घरेलू उत्पाद और विदेशी ऋण का अनुपात 19.2 प्रतिशत के पूर्ण नियंत्रणीय स्तर पर है।

## परिचय

11.1 नई सहस्राब्दी में दो वैश्विक आघातों – पहला आर्थिक आघात और दूसरा, स्वास्थ्य आघात – का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा है। 2007-08 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, चूंकि मुद्रास्फीति के दबाव शांत थे, लंबे समय तक ब्याज दरें बेहद कम थीं, और निवेशक कम अस्थिरता के आदी हो गए थे। 2007-08 में वैश्विक वित्तीय संकट के बाद, चूंकि मुद्रास्फीतिक दबाव मौन थे, लंबे वर्षों तक ब्याज दरें बेहद कम थीं। आसान वित्तीय स्थितियों ने वैश्विक आर्थिक विकास का समर्थन किया, जो 2010 में 4.5 प्रतिशत तक पहुंच गया। अब, कोविड-19 महामारी वैश्विक विकास के लिए एक और आघात है, 2020 में आर्थिक विकास 3.8 प्रतिशत के नकारात्मक स्तर पर आ गया है। अगले दो वर्षों में वैश्विक वस्तु और खाद्य कीमतों में बढ़ोतरी के कारण मुद्रास्फीति की दर कई दशक के उच्च स्तर पर पहुंच गई। रूस-यूक्रेन संघर्ष से मुद्रास्फीति का स्तर और बढ़ गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक प्राधिकरण, विशेष रूप से अमेरिका के फेडरल रिजर्व, “मोनेटरी पालिसी नार्मलाइजेशन” की गति को तेज कर रहे हैं। अमेरिका में 10-वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 2020 के मध्य से 2022 के मध्य तक की अवधि में लगभग छह गुना बढ़ गया है। कई इमर्जिंग मार्किट और फ्रंटियर मार्किट अर्थव्यवस्थाओं से पूंजी को स्थानांतरित करने के लिए जोखिम वाली परिसंपत्तियों को तेजी से बेचा गया जिससे 2020 की अंतिम तिमाही के बाद से विकासशील देशों में लौटने वाले निवल पूंजीगत प्रवाह को रुकते हुए देखा गया।

11.2 अप्रैल 2022 से जोखिम वाली परिसंपत्तियों की ब्याज दरें और कीमतें बेहद अस्थिर रही हैं, जो आर्थिक और नीतिगत स्थिति के बारे में बढ़ी हुई अनिश्चितता को दर्शाती है, तथा जो कम तरलता से और खराब हो गयी है। इमर्जिंग मार्किट देशों (ईएमई) और उच्च उधार लागत का सामना करने वाले प्रमुख उन्नत देशों की मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डॉलर का तेजी से मूल्यवर्धन हुआ है। इस प्रकार, विशेष रूप से अप्रैल 2022 से वैश्विक वित्तीय स्थितियां काफी कठिन हो गई हैं, और जोखिमों का संतुलन काफी नीचे की ओर झुक गया है, जिससे वैश्विक आर्थिक स्थिति कमजोर हो गयी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF)<sup>1</sup> के अनुसार वैश्विक विकास 2021 में 6.0 प्रतिशत से 2022 में 3.2 प्रतिशत और 2023 में 2.7 प्रतिशत तक धीमा होने का अनुमान है। यह वैश्विक वित्तीय संकट और महामारी के तीव्र चरण को छोड़कर 2001 के बाद से सबसे कमजोर विकास प्रतिशत रहा है। इसके अतिरिक्त, विदेशी सार्वजनिक ऋण भेद्यता संबंधी चिंताएं बढ़ रही हैं क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में इस तरह का ऋण रिकॉर्ड स्तर पर है और इसका अधिकांश हिस्सा निजी लेनदारों पर बकाया है, जिसमें से अधिकांश पर परिवर्तनीय ब्याज दरें लागू हैं जो अचानक<sup>2</sup> बढ़ सकती हैं। इस प्रकार, उभरते बाजारों को उच्च विदेशी उधार लागतों, स्थिर उच्च मुद्रास्फीति, अस्थिर कमोडिटी बाजारों, अनिश्चित वैश्विक आर्थिक विकास स्थिति और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में नीति को कसने से फैलने वाले जोखिमों (स्पिलओवर प्रभाव) का सामना करना पड़ता है।

1 वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, आईएमएफ, अक्टूबर 2022।

2 “दक्षिण एशिया की वर्तमान व्यापक आर्थिक चुनौतियाँ और नीतिगत प्राथमिकताएँ”, श्री शक्तिकांत दास, गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक -6 जनवरी 2023 - IMF एशिया और प्रशांत विभाग और प्दक्षिण एशिया क्षेत्रीय प्रशिक्षण द्वारा सह-आयोजित उच्च-स्तरीय सम्मेलन में मुख्य भाषण और तकनीकी सहायता केंद्र, नई दिल्ली

11.3 इस तेजी से विकसित हो रही वैश्विक पृष्ठभूमि में, यह अध्याय निर्यात, आयात, अंतर्राष्ट्रीय निवेश, विदेशी मुद्रा भंडार, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मुद्रा की आवाजाही, विदेशी ऋण और भुगतान संतुलन की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के विदेशी क्षेत्र में विकास का वर्णन करता है। जहां संकेतक उपलब्ध होते हैं, वहां कुछ साथी देशों के साथ इनमें से कुछ संकेतकों की तुलना भी भारत के बाहरी क्षेत्र की स्थिति को उचित परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करने के लिए की जाती है।

### वैश्वीकृत संसार के लाभ उठाने में मददगार व्यापार

11.4 वर्तमान वैश्वीकृत और एकीकृत दुनिया में, उत्पादों और वित्तीय बाजारों के बढ़ते वैश्वीकरण का लाभ प्राप्त करने के लिए विकासशील देशों का व्यापार करना आवश्यक हो गया है। यह अच्छी तरह से माना जाता है कि व्यापार अपने आप में एक अंत नहीं है बल्कि संतुलित, न्यायसंगत और संधारणीय विकास का साधन है। पारंपरिक आर्थिक सिद्धांत संभावित लाभ की ओर इशारा करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए खुलेपन से उभर सकते हैं।

11.5 समय के साथ, विश्व के देशों का व्यापार खुलापन बढ़ रहा है जिसका मापन व्यापार की मात्रा द्वारा जीडीपी के अनुपात के रूप में किया जाता है। विश्व बैंक के डेटाबेस के अनुसार, पूरे विश्व के लिए, विश्व सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यापार का हिस्सा<sup>3</sup> 2003 से 50-60 प्रतिशत की सीमा में रहा है और 2020 में 52 प्रतिशत रहा है। भारत के लिए भी, जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यापार का हिस्सा लगातार बढ़ रहा है, यह 2005 से 40 प्रतिशत के ऊपर रहा है (2020 के महामारी वर्ष को छोड़कर)। यह अनुपात 2021 में 46 प्रतिशत और 2022 की पहली छमाही (H1) के लिए 50 प्रतिशत रहा है।

### वैश्विक परिदृश्य

11.6 कोविड-19-प्रेरित व्यवधानों के बाद, वित्तीय वर्ष 22 में वैश्विक व्यापार संभावनाओं में सुधार हुआ है। रूस-यूक्रेन संघर्ष से प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद, वैश्विक व्यापार ने 2022 की पहली छमाही (H1) में लचीलापन आया है। मजबूत व्यापारिक आयात, विशेष रूप से यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और विकासशील दुनिया के कुछ हिस्सों से उभरते हुए, पहली छमाही (H1) 2022 में पण्य व्यापार के विकास का समर्थन किया। यह आंशिक रूप से महामारी से प्रेरित खर्च के बदलाव तथा संबंधित रुकी हुई मांग को दर्शाता है जिसमें सेवाओं से माल की ओर होता क्रय बदलाव देखा गया है, जो आपूर्ति की बाधाओं के कारण पहले कम हो रहा था। इस प्रवृत्ति में योगदान देने वाले अन्य कारकों में संयुक्त राज्य अमेरिका के मामले में डॉलर की मजबूती, यूरोप में अंतर-क्षेत्रीय व्यापार की सापेक्ष गतिशीलता, और कुछ बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में ऊर्जा की कीमतों<sup>4</sup> में वृद्धि के कारण व्यापार के अनुकूल प्रभाव थे। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के आंकड़ों के अनुसार, वैश्विक व्यापार की मात्रा 2022 की पहली छमाही में 4.8 प्रतिशत बढ़ी, जो 2021 में 9.7 प्रतिशत थी। मूल्य के संदर्भ में वैश्विक पण्य व्यापार साल दर साल बढ़कर, 2021 में 22.2 प्रतिशत हुआ, इसने पिछले तीन वर्षों में देखी गई मंदी को उलट दिया। 2022 की पहली छमाही के दौरान, ट्रेड-इन वैल्यू के संदर्भ में 2019 की इसी अवधि की तुलना में 32 प्रतिशत की वृद्धि हुई।<sup>5</sup>

11.7 हालांकि, प्रतिकूल कारकों के संगम के कारण 2022 की दूसरी छमाही (H2) में वैश्विक व्यापार स्थिति गंभीर हो गयी है, जिसमें प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मंदी की बढ़ती संभावना और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में कमी; कई केंद्रीय बैंकों की सख्त आक्रामक मौद्रिक नीति; अव्यवस्थित वित्तीय स्थिति; आपूर्ति-श्रृंखला

3 सकल घरेलू उत्पाद के हिस्से के रूप में मापी गई वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात और आयात का योग व्यापार है

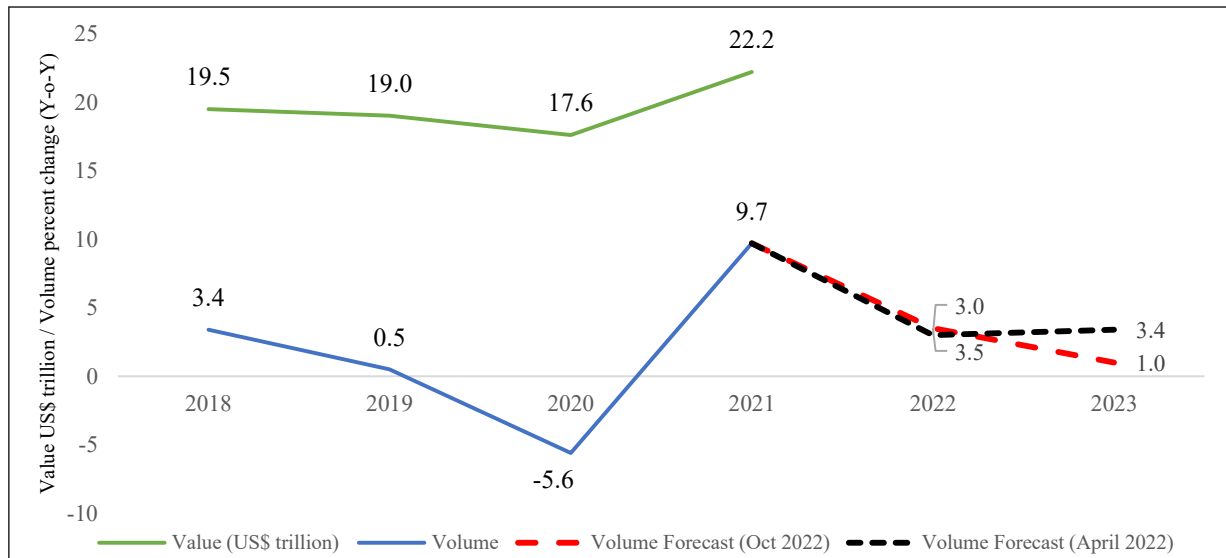
4 संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी), ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स इन फ्रेंचरड वर्ल्ड: ग्लोबल डिसऑर्डर एंड रीजनल रेस्पॉन्स, अक्टूबर 2022।

5 वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन प्रेस रिलीज, इंटरनेशनल ट्रेड स्टैटिस्टिक्स, 5 अक्टूबर 2022

में निरंतर व्यवधान और बढ़ा हुआ भाड़ा शुल्क शामिल है। वैश्विक व्यापार के प्रमुख संकेतक जैसे मालसूची और नए निर्यात आदेश इन प्रतिकूल घटनाओं की गवाही देते प्रतीत होते हैं। 28 नवंबर 2022 को जारी डब्ल्यूटीओ गुड्स ट्रेड बैरोमीटर<sup>6</sup> के अनुसार, 2022 के समापन महीनों और 2023 में व्यापार वृद्धि धीमी होने की संभावना है, क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था मजबूत विपरीत परिस्थितियों से जूझ रही है। 96.2 का वर्तमान मान सूचकांक के आधार मान तथा पिछले मान 100.0 दोनों से नीचे है, जो ट्रेडेड गुड्स(व्यापारिक सामान) की मांग में मंदी को दर्शाती है।

11.8 इस प्रकार, भविष्य के व्यापार अनुमानों के संबंध में, विश्व व्यापार संगठन के अनुसार, विश्व व्यापार के 2022 की दूसरी छमाही में गति खोने और 2023 में कमजोर रहने की उम्मीद है। संगठन का अनुमान है कि वैश्विक व्यापार 2023 में केवल 1 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है, जो कि 3.4 प्रतिशत के पिछले अनुमान से तेजी से होने वाली गिरावट है।<sup>7</sup> हालांकि, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में मौद्रिक नीति में बदलाव और रूस-यूक्रेन संघर्ष की अप्रत्याशित प्रकृति के कारण पूर्वानुमान के साथ उच्च स्तर की अनिश्चितता जुड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) ने दिसंबर 2022 की अपनी वैश्विक व्यापार रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि वर्तमान व्यापार मंदी के 2023 तक और खराब होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, जबकि वैश्विक व्यापार के लिए स्थिति अनिश्चित बनी हुई है, नकारात्मक कारक सकारात्मक प्रवृत्तियों से अधिक प्रबल प्रतीत हो रहे हैं।

चित्र XI. 1: वैश्विक पण्य व्यापार में वृद्धि: वास्तविक और पूर्वानुमान



स्रोत: विश्व व्यापार संगठन

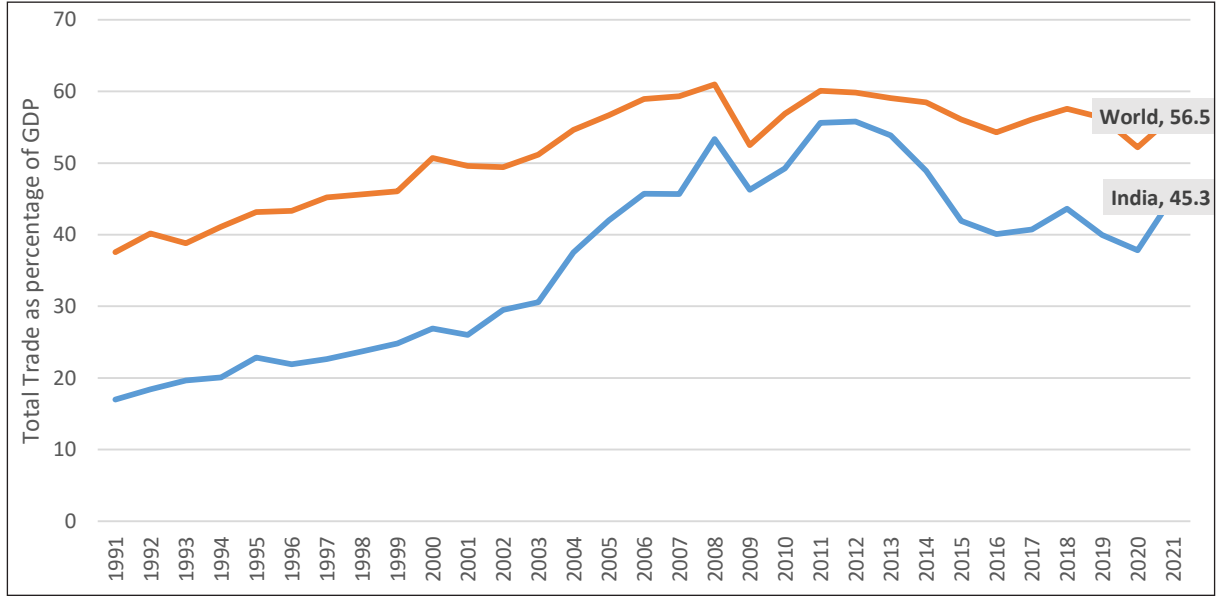
### भारत का वैविध्य होता और बढ़ता व्यापार

11.9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भारत के विदेशी क्षेत्र के लचीलेपन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यापार 1980 के दशक में 12-15 प्रतिशत; 1990 के दशक में 16-25 प्रतिशत और 2000 के दशक में 25-50 प्रतिशत की सीमा में था। आगामी पैराग्राफों में भारत के व्यापार निष्पादन का विस्तृत विश्लेषण किया गया है।

6 विश्व व्यापार संगठन ने विश्व व्यापार के रुझानों पर रियल टाइम(तात्कालिक)<sup>6</sup> जानकारी प्रदान करने के लिए संकेतकों का एक सेट विकसित किया है। गुड्स ट्रेड बैरोमीटर एक प्रमुख संकेतक है जो पण्य व्यापार मात्रा के आंकड़ों से दो से तीन महीने पहले विश्व व्यापार वृद्धि में बदलाव का संकेत देता है। 100 से अधिक मान ऊपर-प्रवृत्ति विस्तार का संकेत देते हैं जबकि 100 से कम मूल्य नीचे-प्रवृत्ति वृद्धि का संकेत देते हैं।

7 विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की 5 अक्टूबर, 2022 की प्रेस विज्ञप्ति।

चित्र XI. 2: भारतीय व्यापार वैश्विक व्यापार स्तरों के साथ गति पकड़ रहा है



स्रोत: विश्वबैंक डेटाबेस

तालिका XI. 1: भारत के व्यापार के प्रमुख पहलू (कैलेंडर वर्षवार)

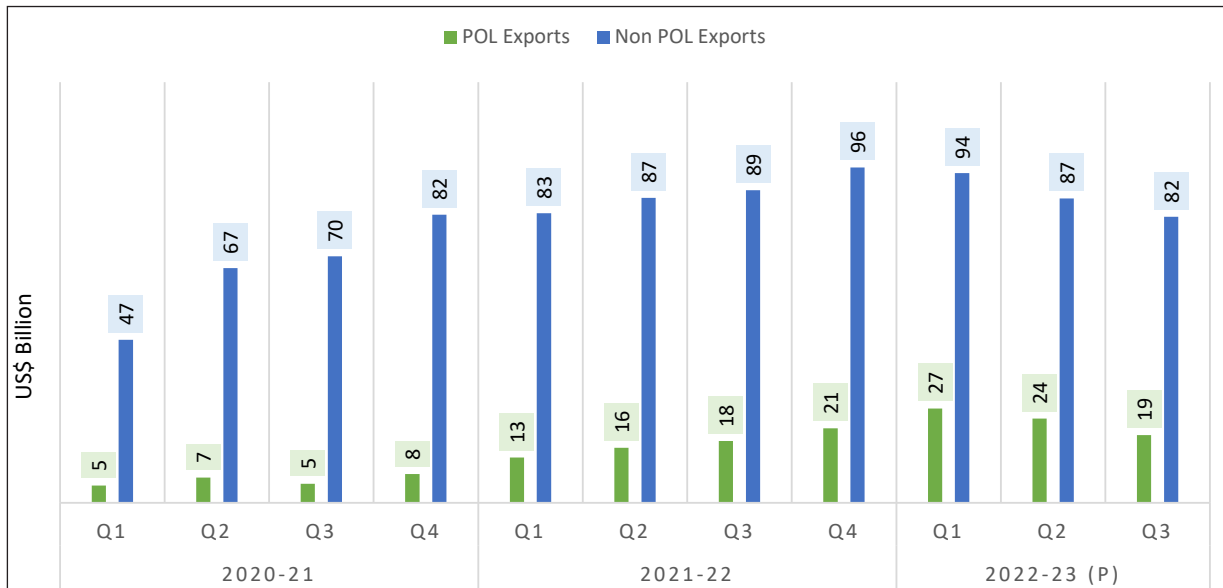
	2019	2020	2021
<b>निर्यात निष्पादन (प्रतिशत में)</b>			
विश्व पण्य निर्यात (वर्ल्ड मर्चेडाइज एक्सपोर्ट्स) में हिस्सेदारी	1.7	1.6	1.8
विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में हिस्सेदारी	3.5	4.0	4.0
विश्व पण्य और सेवा निर्यात (वर्ल्ड मर्चेडाइज प्लस सर्विसेज एक्सपोर्ट्स) में हिस्सेदारी	2.1	2.1	2.2
<b>आयात निष्पादन (प्रतिशत में)</b>			
विश्व पण्य आयात (वर्ल्ड मर्चेडाइज इंपोर्ट) में हिस्सेदारी	2.5	2.1	2.5
विश्व वाणिज्यिक सेवाओं के आयात में हिस्सेदारी	3.0	3.2	3.5
विश्व पण्य और सेवा आयात (वर्ल्ड मर्चेडाइज प्लस सर्विसेज इंपोर्ट) में हिस्सेदारी	2.6	2.3	2.7
<b>विश्व व्यापार में भारत का स्थान</b>			
पण्य निर्यात	18	21	
पण्य आयात	10	14	
सेवा निर्यात	8	7	
सेवा आयात	10	10	

स्रोत: विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) मासिक विदेश व्यापार सांख्यिकी, नवंबर 2022 (अक्टूबर 2022 तक के आंकड़ों पर आधारित)

## पण्य व्यापार की प्रवृत्ति

11.10 वित्त वर्ष 22 में भारत ने 422.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सर्वकालिक उच्च वार्षिक व्यापारिक निर्यात हासिल किया है। हालाँकि, वैश्विक अर्थव्यवस्था ने घोर विपरीत परिस्थितियों का सामना करना शुरू कर दिया है और वैश्विक व्यापार मंदी की लहरों ने भारत के पण्य निर्यात वृद्धि को प्रभावित करना शुरू कर दिया है, और 2022 में इसकी गति में कमी देखी गई है। घ अप्रैल-दिसम्बर 2022 में पण्य निर्यात 332.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-दिसम्बर 2021 की अवधि के दौरान यह 305.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-दिसम्बर 2022 तक गैर-पेट्रोलियम और गैर-रत्न/आभूषण निर्यात 233.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-दिसम्बर 2021 में यह 230.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वित्त वर्ष 23 (दिसम्बर 2022 तक) के दौरान पेट्रोलियम, आयल और लुब्रिकेंट(पीओएल) का निर्यात लगभग 21.1 प्रतिशत और गैर-पीओएल निर्यात कुल निर्यात का 78.9 प्रतिशत था। वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण, वित्त वर्ष 22 (अप्रैल-दिसम्बर 2022) में पेट्रोलियम उत्पादों का सबसे अधिक निर्यात किया जाना जारी रहा, इसके बाद रत्न और आभूषण, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, और ड्रग्स /फार्मास्यूटिकल्स का स्थान रहा (सांख्यिकीय परिशिष्ट की सारणी 6.3 क और ख)

चित्र XI.3: भारत का पण्य निर्यात



स्रोत: वाणिज्य विभाग

नोट: P: अनंतिम

## भारत के व्यापार निष्पादन में बेहतर स्पॉट

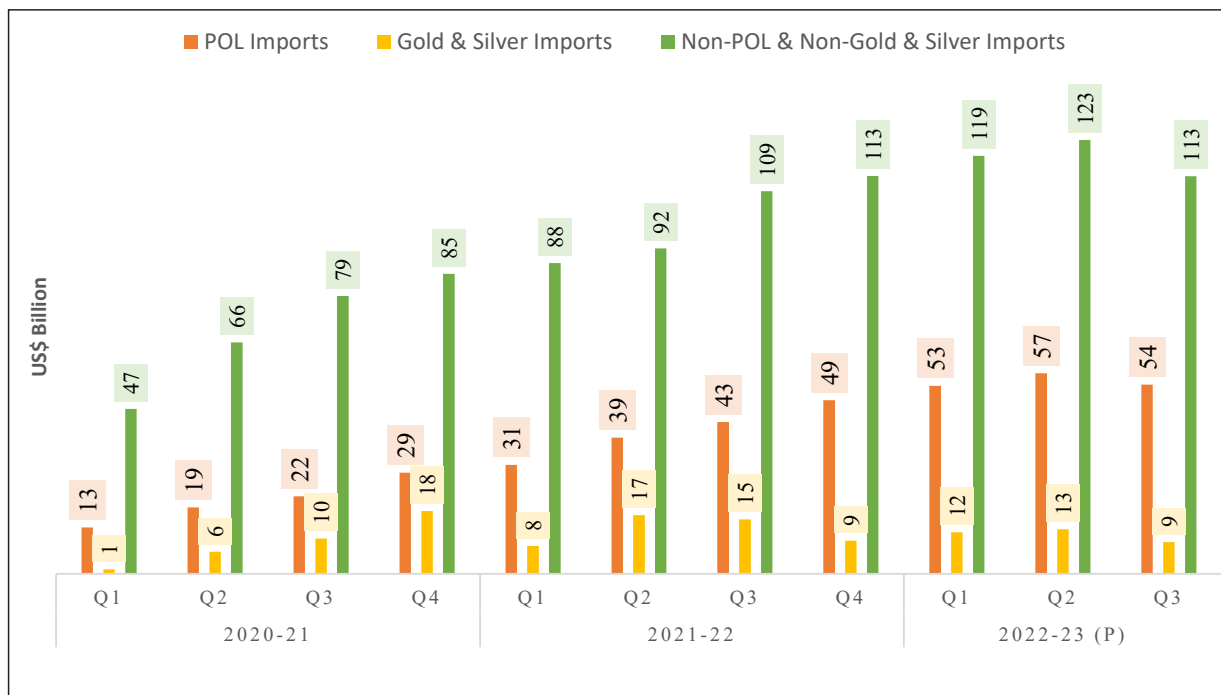
11.11 वित्त वर्ष 22 में ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान और जैविक और अकार्बनिक रसायन क्षेत्रों के निर्यात में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की गई। वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही की वैश्विक विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इन क्षेत्रों ने अपनी विकास गति को बनाए रखा है। आपूर्ति श्रृंखला में कोविड के प्रभाव के बावजूद फार्मा निर्यात में वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2015 में भारत का फार्मा निर्यात 15.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 22 में 24.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल का निर्यात 18.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो अप्रैल-दिसंबर 2021 की तुलना में 3.6 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करता है। निर्यात में उच्च वृद्धि दुनिया भर के देशों द्वारा दवाओं की सूची के स्टॉकिंग और कोविड-19 महामारी से संबंधित टीकों और दवाओं की बढ़ती मांग के कारण थी,

जिसकी पूर्ति करने में भारत सक्षम था। भारत के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में भी लगातार वृद्धि हो रही है। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात, जो वित्त वर्ष 19 तक 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से नीचे रहा, अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान 11.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 51.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। इंजीनियरिंग सामान का निर्यात वित्त वर्ष 22 में पहली बार 100 अरब अमेरिकी डॉलर के आंकड़े को पार कर गया। वित्त वर्ष 22 में जैविक और अकार्बनिक रसायनों के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान 23.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है।

11.12 महामारी के कम होने के साथ, भारत की घरेलू मांग में सुधार देखा गया, जिसके परिणामस्वरूप आयात में अच्छी वृद्धि हुई। अप्रैल-दिसंबर 2022 की अवधि के लिए पण्य आयात 551.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि अप्रैल-दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान यह 441.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। प्रमुख आयात वस्तुओं में, अप्रैल-दिसंबर 2022 में पेट्रोलियम कच्चा तेल एवं उत्पाद का आयात 45.6 प्रतिशत बढ़कर 163.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि वित्तीय वर्ष 22 के अप्रैल-दिसंबर 2021 तक यह 112.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था और यह उच्चतम आयातित वस्तु बना रहा।

11.13 ऊर्जा की मांग कोयले और पेट्रोलियम ऑयल एवं लोहक (पीओएल) सहित हमारे ईंधन आयात को बढ़ा सकती है, जिसका हिस्सा अप्रैल-दिसंबर 2022 में बढ़ कर कुल आयात में 37.1 प्रतिशत हो गया, जो पिछले साल इसी अवधि में 30.4 प्रतिशत था। अन्य प्रमुख आयातों में शामिल हैं-इलेक्ट्रॉनिक सामान, कोयला, कोक और ब्रिकेट, मशीनरी (इलेक्ट्रिकल और गैर-इलेक्ट्रिकल), और जैविक व अकार्बनिक रसायन (सांख्यिकीय परिशिष्ट की सारणी 6.2 क और ख)।

चित्र XI.4: भारत का पण्य आयात

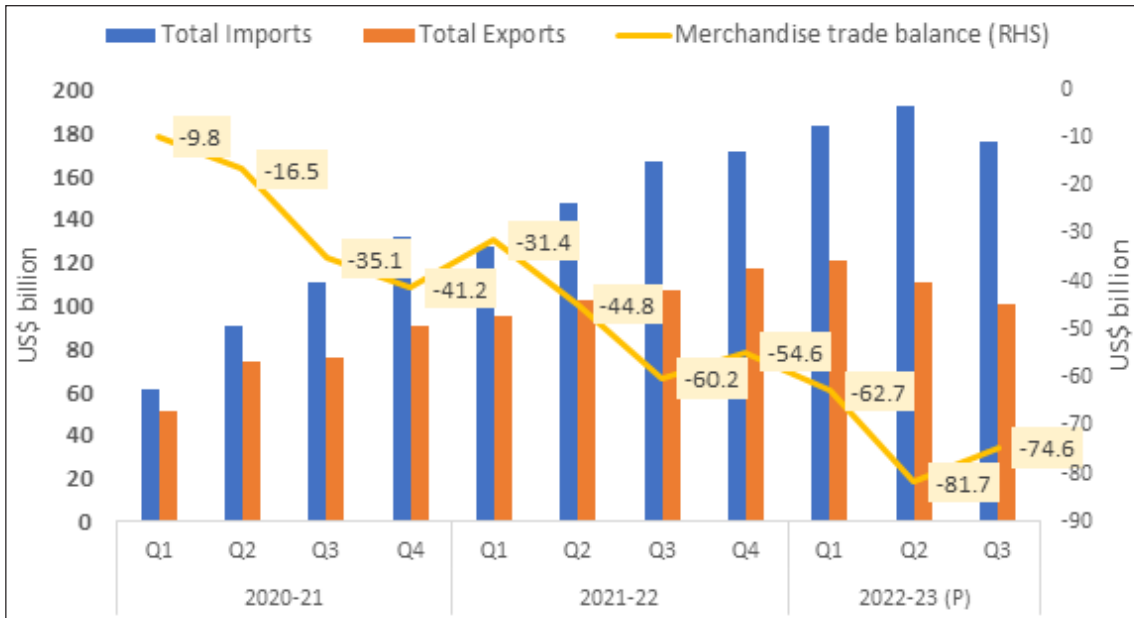


स्रोत: वाणिज्य विभाग

नोट: P: अनंतिम

11.14 अप्रैल-दिसंबर 2022 के लिए पण्य व्यापार घाटा 218.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने का अनुमान लगाया गया था, जबकि अप्रैल-दिसंबर 2021 में यह 136.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

चित्र XI.5: पण्य का आयात, निर्यात और व्यापार संतुलन की प्रवृत्ति



स्रोत: वाणिज्य विभाग P: अनंतिम

11.15 संयुक्त राज्य अमेरिका अप्रैल-नवंबर, 2022 में और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड शीर्ष निर्यात गंतव्य बना रहा। भारत के निर्यात पार्टनर के रूप में नीदरलैंड ने चीन को तीसरे स्थान से हटा दिया। भारत के निर्यात स्थलों में विविधता देखी गयी है। उदाहरण के लिए, कुल निर्यात में दक्षिण अफ्रीका की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 19 में 1.2 प्रतिशत से बढ़कर वित्त वर्ष 23 (अप्रैल से नवंबर) में 2.0 प्रतिशत हो गई है। इसी अवधि में, ब्राजील की हिस्सेदारी 1.2 प्रतिशत से बढ़कर 2.5 प्रतिशत और सऊदी अरब की हिस्सेदारी 1.7 प्रतिशत से बढ़कर 2.3 प्रतिशत हो गई है। आयात के संबंध में, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और सऊदी अरब का भारत के कुल आयात में 40 प्रतिशत का संयुक्त हिस्सा है। हालांकि, अप्रैल-नवंबर 2022 के दौरान चीन की हिस्सेदारी एक साल पहले के 15.5 प्रतिशत से घटकर 13.8 प्रतिशत रह गई। इसी तरह, अप्रैल-नवंबर 2022 में यूएसए की हिस्सेदारी एक साल पहले के 7.2 प्रतिशत से घटकर 6.9 प्रतिशत हो गई (सांख्यिकीय परिशिष्ट में तालिका 6.4 देखें)।

### सेवाओं का व्यापार

11.16 भारत ने वित्त वर्ष 22 में विश्व सेवा व्यापार में अपना प्रभुत्व बनाए रखा। महामारी से प्रेरित वैश्विक प्रतिबंधों और कमजोर पर्यटन राजस्व के बावजूद, वित्त वर्ष 22 में भारत का सेवा निर्यात 254.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जो वित्त वर्ष 21 की तुलना में 23.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है और वित्त वर्ष 22 की समान अवधि के मुकाबले अप्रैल-सितंबर 2022 में 32.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सॉफ्टवेयर और व्यावसायिक सेवाएं मिलकर भारत के कुल सेवा निर्यात का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बनाती हैं और वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही के दौरान मजबूत वृद्धि दर्शाती हैं। जहाँ रिटेल और उपभोक्ता व्यवसाय, संचार और मीडिया, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग, वित्तीय और बीमा सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कंपनियों के मजबूत राजस्व ने सॉफ्टवेयर निर्यात में वृद्धि को बढ़ावा दिया, वहां तिमाही के दौरान इंजीनियरिंग, और अनुसंधान/विकास संबंधी सेवाओं में महत्वपूर्ण वृद्धि ने व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में वृद्धि को बढ़ावा दिया।

11.17 वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 21 के बीच सेवाओं का आयात 25.1 प्रतिशत बढ़कर 147.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और वित्त वर्ष 22 की इसी अवधि की तुलना में अप्रैल-सितंबर 2022 में 36.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सेवाओं के आयात में वृद्धि मुख्य रूप से परिवहन सेवाओं, यात्रा और अन्य



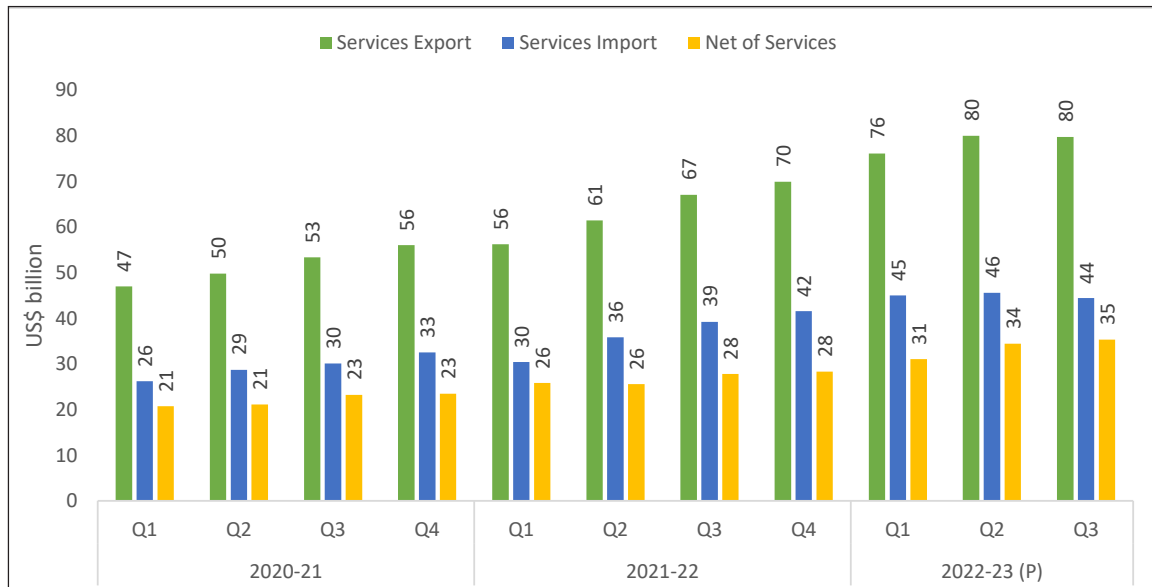
व्यावसायिक सेवाओं के भुगतान के कारण हुई है। वैश्विक गतिविधि की बहाली के बाद, शिपिंग वेसल की कमी और उच्च परिवहन लागत के परिणामस्वरूप परिवहन भुगतान में वृद्धि हुई। यात्रा प्रतिबंधों में ढील के बाद यात्रा आयात में वृद्धि देखी गई।

तालिका: XI.2: सेवा व्यापार का लचीला प्रदर्शन (मूल्य अमेरिकी डॉलर बिलियन में)

	2020-21		2021-22		अप्रैल-सितंबर 2022 (अनंतिम)	
	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात	आयात
<b>सेवाएं</b>	<b>206.1</b>	<b>117.5</b>	<b>254.5</b>	<b>147.0</b>	<b>156.1</b>	<b>90.6</b>
दूसरों के स्वामित्व वाली भौतिक निविष्टियों पर विनिर्माण सेवाएँ	0.3	0.03	0.5	0.1	0.6	0.1
रखरखाव और मरम्मत सेवाएँ एनआईई	0.2	0.8	0.2	1.4	0.1	1.0
परिवहन	21.9	19.8	32.7	35.8	19.4	23.1
यात्रा	8.5	11.5	9.1	16.3	10.5	13.8
सन्निर्माण	2.6	2.6	2.6	2.9	1.6	1.6
बीमा और पेंशन सेवाएँ	2.4	2.1	3.3	2.1	1.7	1.1
वित्तीय सेवाएँ	4.3	4.8	5.5	5.6	3.8	3.1
बौद्धिक संपदा के उपयोग के लिए शुल्क एनआईई	1.3	7.7	0.8	9.0	0.7	4.5
दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएँ	103.1	12.3	125.6	14.5	72.6	8.6
अन्य व्यापार सेवाएँ	49.2	49.5	58.9	51.7	36.9	28.3
व्यक्तिगत, सांस्कृतिक और मनोरंजक सेवाएँ	2.3	2.8	3.2	4.5	1.9	2.9
सरकारी सामान और सेवाएँ एनआईई	0.6	1.0	0.8	0.9	0.4	0.4
अन्य एनआईई	9.5	2.6	11.3	2.2	6.1	2.2

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, भुगतान संतुलन विवरण

चित्र XI.6: सेवा व्यापार में तेजी का रुझान



स्रोत: वाणिज्य विभाग; P: अनंतिम

11.18 जहाँ 2022 की दूसरी छमाही में पण्य निर्यात में कुछ मंदी देखी जा रही है, वहीं भारत का सेवा निर्यात मजबूत रहा है। चूंकि भारत कम लागत पर ज्ञान-आधारित सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए वैश्विक आर्थिक मंदी और निकट भविष्य की प्रतिकूल स्थिति में भी उसकी मांग कम नहीं होगी। सेवा क्षेत्र निर्यात में अप्रैल-दिसंबर 2021 के 184.7 बिलियन यूएस डॉलर के मूल्य की तुलना में अप्रैल-दिसंबर, 2022 में 235.8 बिलियन यूएस डॉलर का अनुमानित मूल्य रहा। पिछले वर्ष की इसी अवधि के सेवा क्षेत्र के आयात के अनुमानित मूल्य 105.5 बिलियन डॉर की तुलना में अप्रैल-दिसंबर 2022 में 135.0 बिलियन डॉलर हो गया। सेवा क्षेत्र द्वारा समर्थित, अप्रैल-दिसंबर 2022 में भारत का समग्र निर्यात (पण्य और सेवाएँ दोनों मिलकर) 568.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 16.1 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है। अप्रैल-दिसंबर 2022 में कुल आयात 686.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 25.6 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।

### विदेश व्यापार नीति

11.19 भारत की विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) परंपरागत रूप से एक बार में पांच साल के लिए तैयार की जाती है। एफटीपी का उद्देश्य निर्यात और आयात के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का ढांचा प्रदान करना और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं का समुच्चय प्रदान करना है। 2015-2020 के लिए भारत की नवीनतम विदेश व्यापार नीति (FTP) वर्तमान में प्रचलन में है। महामारी की अवधि के दौरान नीतिगत स्थिरता प्रदान करने के लिए, पांच वर्षीय एफटीपी 2015-20 को 2020 से 2022 तक बढ़ा दिया गया था। अस्थिर वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक स्थितियों और मुद्रा में अस्थिरता के कारण नीति को मार्च 2023 तक आगे बढ़ा दिया गया है। इस अवधि के दौरान, सरकार महत्वपूर्ण उपाय कर रही है और लगातार उत्पादों के साथ-साथ संभावित बाजारों तक निर्यात में विविधता लाने के अवसरों की तलाश कर रही है। सरकार सक्रिय रूप से व्यापार समझौतों को सुविधाजनक बनाने और विभिन्न हितधारकों के परामर्श को लेकर योजनाएं शुरू करने पर काम कर रही है। वर्ष 2022 में, भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका उद्देश्य पण्य(माल) और सेवाओं पर टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं में कमी के द्वारा अधिक बाजार पहुंच प्रदान करना और निर्यातकों को प्रतिस्पर्धी बनाना है। राज्यों के सम्भाव्य साधन और क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक<sup>8</sup> भी शुरू किया गया है। यह राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में सभी हितधारकों का मार्गदर्शन करेगा।

### भारतीय रुपये में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता

11.20 जुलाई 2022 में, भारतीय रिजर्व बैंक(आरबीआई) ने भारत से निर्यात पर जोर देने के साथ-साथ वैश्विक व्यापार के विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रुपये (INR) में इनवॉइस, भुगतान और निर्यात/आयात के निपटान के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की अनुमति देते हुए परिपत्र जारी किया जिससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भारतीय रुपये (INR) में वैश्विक व्यापारिक समुदाय की बढ़ती रुचि को समर्थन दिया जा सके। इस ढांचे में भारतीय रुपये में निर्यात और आयात का इनवॉइस, व्यापारिक भागीदार देशों की मुद्राओं के बीच बाजार-निर्धारित विनिमय दर और भारत में अधिकृत डीलर बैंकों के साथ खोले गए विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों<sup>9</sup> के माध्यम से निपटान शामिल है।

<sup>8</sup> नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ साझेदारी में चुनौतियों और अवसरों की पहचान करने, सरकारी नीतियों की प्रभावशीलता में वृद्धि; और एक सुविधाजनक नियामक ढांचे को प्रोत्साहित करने के लिए एक निर्यात तत्परता सूचकांक(ईपीआई) तैयार किया है। ईपीआई की संरचना में 4 स्तंभ - नीति; व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र; निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र; निर्यात निष्पादन और 11 उप-स्तंभ - निर्यात प्रोत्साहन नीति; संस्थागत ढांचा; व्यापारिक वातावरण; आधारभूत संरचना; परिवहन कनेक्टिविटी; ऋण सुविधा; निर्यात अवसंरचना; व्यापार समर्थन; अनुसंधान और विकास अवसंरचना; निर्यात विविधीकरण; और विकास-उन्मुखता सम्मिलित हैं।

<sup>9</sup> वोस्ट्रो खाता वह खाता होता है जो घरेलू बैंक, 'घरेलू बैंक की मुद्रा अर्थात रुपये' में किसी अन्य विदेशी बैंक के लिए रखता है। ऐसे खाते घरेलू बैंकों को अपने उन ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाते हैं जिनकी वैश्विक बैंकिंग आवश्यकताएं होती हैं।

11.21 निपटान के लिए इस व्यवस्था के अंतर्गत, (क) इस तंत्र के माध्यम से आयात करने वाले भारतीय आयातकों को भारतीय रुपये में भुगतान करना होगा, जो विदेशी आपूर्तिकर्ता/विक्रेता से सेवाओं/माल की आपूर्ति के इनवॉइस के अनुसार भागीदार देश के प्रतिनिधि बैंक के विशेष वोस्ट्रो खाते में जमा किया जाएगा। जबकि (ख) इस तंत्र के माध्यम से माल और सेवाओं का निर्यात करने वाले भारतीय निर्यातकों को भागीदार देश के प्रतिनिधि बैंक के निर्दिष्ट विशेष वोस्ट्रो खाते में शेष राशि से भारतीय रुपये में निर्यात मूल्य का भुगतान किया जाएगा।

11.22 अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आक्रामक तरीके से पालिसी दरों में बढ़ोतरी और उसका आक्रामक (हॉकिश) रवैया के साथ अमेरिकी डॉलर की बहु-दशकों के उच्च स्तर पर वापसी, और भारतीय रुपये सहित विभिन्न उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (EME) की मुद्राओं का सहवर्ती कमजोर होने की पृष्ठभूमि के सामने भारतीय रुपये में अंतरराष्ट्रीय निपटान के लिए उपर्युक्त तंत्र बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ है। यह तंत्र, चालू खाते से संबंधित व्यापार प्रवाह, विशेष रूप से अमेरिकी डॉलर के निपटान में, विदेशी मुद्रा की शुद्ध मांग को काफी हद तक कम कर सकता है। इसके अलावा, सीमा पार व्यापार में भारतीय रुपये के उपयोग से भारतीय व्यवसायों के लिए मुद्रा जोखिम कम होने की उम्मीद है। मुद्रा की अस्थिरता से सुरक्षा न केवल व्यवसाय करने की लागत को कम करती है बल्कि बेहतर व्यावसायिक विकास को भी सक्षम बनाती है, जिससे भारतीय व्यवसायों के वैश्विक स्तर पर बढ़ने की संभावना में सुधार होता है। यह विदेशी मुद्रा भंडार रखने की आवश्यकता और विदेशी मुद्रा पर निर्भरता को भी कम करता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी आर्थिक आघात (अर्थ व्यवस्था परिवर्तनों) के प्रति कम संवेदनशील हो जाती है।<sup>10</sup> इसके अलावा, यह भारतीय निर्यातकों को विदेशी ग्राहकों से भारतीय रुपये में अग्रिम भुगतान प्राप्त करने में सहायता कर सकता है और जब रुपया निपटान तंत्र समय के साथ गति प्राप्त कर लेगा तब लंबी अवधि में, यह भारतीय रुपये को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के रूप में भी बढ़ावा देगा। किसी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा के उद्भव के लिए पूर्वापेक्षाओं में एक शर्त यह है कि उस मुद्रा का व्यापार इनवॉइस में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाए। विदेशी मुद्रा बाजार कारोबार (दैनिक औसत) के संदर्भ में, बीआईएस त्रैवार्षिक सेंट्रल बैंक सर्वे 2022 के अनुसार, अमेरिकी डॉलर डोमिनेंट व्हीकल करेंसी है, जिसमें 88 प्रतिशत वैश्विक विदेशी मुद्रा कारोबार होता है। भारतीय रुपए की हिस्सेदारी 1.6 फीसदी थी। यदि भारतीय रुपये का कारोबार 4 प्रतिशत के वैश्विक विदेशी मुद्रा कारोबार में गैर-अमेरिकी, गैर-यूरो मुद्राओं के हिस्से के बराबर हो जाता है, तो भारतीय रुपये को एक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा माना जा सकता है, जो वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति को दर्शाता है।<sup>11</sup>

## व्यापार बढ़ाने की पहल

11.23 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य से अधिक, वित्तवर्ष-22 में 422.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारत के निर्यात का सराहनीय प्रदर्शन, सभी क्षेत्रों और सभी हितधारकों के प्रयासों का परिणाम रहा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अग्रणी कारकों में से कुछ लक्ष्य सरकार द्वारा निर्धारित किए गए थे, जिनमें - देश-वार, उत्पाद-वार और निर्यात संवर्धन परिषद-वार विनिर्दिष्ट लक्ष्यों का निर्धारण; लक्ष्यों का मॉनिटरिंग और जहां आवश्यकता हो वहां प्रक्रिया में सुधार करना सम्मिलित था। पेट्रोलियम, सूती धागे, कपड़ा, रसायन और इंजीनियरिंग सामान जैसे उत्पादों की मांग में वृद्धि से निर्यात वृद्धि प्रेरित थी। भारत महामारी से संबंधित व्यवधानों के मद्देनजर कुछ उत्पादों की आपूर्ति में अंतर का लाभ उठाने और वैश्विक मांग को पूरा करने में सक्षम था। अनुकूल वैश्विक पण्य कीमतों से निर्यात को भी सहायता मिली। सरकार की कुछ विशिष्ट योजनाएँ जो निर्यात को सुविधाजनक बना रही हैं व प्रोत्साहित कर रही हैं तथा करती आ रही हैं, वे इस प्रकार हैं।

11.24 **कृषि उत्पादों पर बल देना:** प्रभावी कृषि निर्यात नीति द्वारा समर्थित भारत का कृषि निर्यात वित्त वर्ष 22 में अब तक का सर्वाधिक निर्यात 37.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया और इसने अप्रैल-नवंबर

<sup>10</sup> 20 अक्टूबर 2022 को मुंबई में नॉरेन एक्सचेंज डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (FEDAI) के वार्षिक दिवस समारोह में श्री टी रवी शंकर, डिप्टी गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया मुख्य भाषण।

<sup>11</sup> पात्रा, एम. डी (2022): India/75, भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, अगस्त, प्रिंटेड पेज 13-34।

2022 के दौरान US\$ 26.8 बिलियन के निर्यात के साथ वित्त वर्ष 23 में अच्छा प्रदर्शन करना जारी रखा। निर्यात निरीक्षण परिषद (EIC), वृक्षारोपण बोर्ड, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) सहित निर्यात संवर्धन एजेंसियों के सक्रिय समर्थन, निर्यात के लिए आवश्यक प्रमाणपत्रों को ऑनलाइन जारी करने जैसे निर्यात सुविधा उपायों ने कृषि निर्यात के विकास में सहायता की है। व्यापार मेलों में भागीदारी और भारतीय मिशनों के सहयोग के विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि उत्पादों के लिए नियमित प्रचार-प्रसार किया गया।

जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के संघ शासित प्रदेशों से कृषि निर्यात शुरू करने के लिए, एपीडा ने कश्मीर घाटी के स्टार्ट-अप, नए उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठन/किसान समूहों और क्षेत्र के निर्यातकों को आयातकों के साथ जोड़ा है। मध्य पूर्व, यूरोपीय संघ और उत्तरी अमेरिका जैसे गंतव्यों के लिए उच्च मूल्य वाले कश्मीर केसर (जीआई) की नियमित शिपमेंट हो रही है।

**11.25 ब्याज समानीकरण योजना:** यह योजना बैंकों द्वारा निर्यातकों को उनके प्री- और पोस्ट-शिपमेंट रुपया निर्यात क्रेडिट पर ब्याज दरों में लाभ देने के लिए तैयार की गई थी। योजना का विस्तार करते हुए 1 अक्टूबर 2021 से सबवेंशन (सरकारी अनुदान) दरों में भी कमी की गई है। अब से, एमएसएमई विनिर्माण निर्यातकों के लिए 3 प्रतिशत (पहले 5 प्रतिशत) सबवेंशन की घटी हुई संशोधित दरें और 410 (पूर्ववर्ती 416) एचएस लाइनों के साथ निर्यात करने वाले व्यापारी और अन्य निर्माता निर्यातकों पर 2 प्रतिशत (पहले 3 प्रतिशत) की दर लागू होती है।

**11.26 निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट ( आरओडीटीईपी ) योजना:** यह योजना केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर विभिन्न चरणों में उन केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों/करों/लेवी की छूट देती है जो निर्यातित उत्पादों के निर्माण और वितरण की प्रक्रिया में खर्च किए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में इन्हें किसी अन्य शुल्क छूट योजना के तहत धन वापस नहीं की जा रही है।

**11.27 निर्यात ऋण गारंटी:** निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) निर्यात ऋण बीमा सेवाएं देकर भारतीय निर्यातकों और बैंकों की सहायता करता है। ईसीजीसी निर्यातकों को भुगतान जोखिमों के परिणामों से बचाने के लिए निर्यात माल पर बीमा सुरक्षा देता है। यह बैंकों को निर्यात ऋण बीमा (ईसीआईबी) भी देता है ताकि बैंकों को दिवालियापन के जोखिम और/या निर्यातक उधारकर्ता की दीर्घकालीन चूक के कारण निर्यातकों को दिए गए निर्यात ऋण के कारण होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। इस योजना के तहत ईसीआईबी के अधीन ईसीजीसी ने जुलाई 2022 में नई योजना प्रारंभ की है। छोटे निर्यातकों की सहायता करने के लिए ₹20 करोड़ की निर्यात कार्यशील पूंजी सीमा वाले खातों को प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट ऋण प्रदान करने वाले बैंकों का बीमा कवर जुलाई 2022 में 70 प्रतिशत के औसत कवरेज से बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है।

**11.28 कृषि उड़ान योजना:** कृषि उत्पादों के परिवहन में किसानों की सहायता करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मार्गों पर अगस्त 2020 में कृषि उड़ान योजना शुरू की गई थी ताकि उनके मूल्य की प्राप्ति में सुधार हो सके। कृषि उड़ान 2.0 को अक्टूबर 2021 में मौजूदा प्रावधानों को बढ़ाते हुए प्रारंभ किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तर-पूर्वी राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों से खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के परिवहन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई परिवहन द्वारा कृषि उपज की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए, लैंडिंग, पार्किंग शुल्क, टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग शुल्क और भारतीय मालवाहकों और यात्री-से-कार्गो विमान के लिए मुख्य रूप से उत्तर पूर्व, पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में लगभग 25 हवाई अड्डों और अन्य क्षेत्रों में 28 हवाई अड्डे के निकट मार्ग नेविगेशन सुविधा शुल्क की पूर्ण छूट देता है। इसके अलावा, योजना के तहत पांच और हवाई अड्डों को शामिल करने पर इनकी संख्या 58 हो गई है।

11.29 **निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना:** सरकार राज्यों से निर्यात के विकास के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचे के निर्माण में केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों की सहायता के लिए वित्त वर्ष 18 से निर्यात योजना के लिए व्यापार अवसंरचना (टीआईईएस) को लागू कर रही है। योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्यात अवसंरचना की स्थापना या उन्नयन के लिए केंद्र/राज्य सरकार की स्वामित्व वाली एजेंसियों को सहायता अनुदान के रूप में यह योजना वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

11.30 **निर्यात केंद्र के रूप में जिला एक जिला एक उत्पाद पहल:** निर्यात केंद्र के रूप में जिला-ओडीओपी पहल का उद्देश्य सामान्य जनता के लिए निर्यात प्रोत्साहन, विनिर्माण और रोजगार सृजन को लक्षित करना है जिससे भारत को एक निर्यात महाशक्ति बनाने में राज्यों और जिलों को सार्थक हितधारक व सक्रिय भागीदार बनाया जा सके इस प्रकार आत्मनिर्भर मिशन में योगदान दिया जाए और स्थानीय वस्तुओं के प्रचार से दुनिया में 'मेक इन इंडिया' की संकल्पना को मूर्तरूप दिया जा सके। इस पहल का उद्देश्य देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना भी है। इसका उद्देश्य सभी क्षेत्रों में समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सक्षम करने, विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिले में निवेश आकर्षित करने में देश के प्रत्येक जिले से उत्पाद/उत्पादों/सेवाओं तथा ब्रांड का चयन और प्रचार करना है। निर्यात केंद्रों के रूप में जिलों पर ध्यान केंद्रित करके निर्यात पर जोर देने से भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला के साथ और अधिक निकटता से एकीकृत किया जा सकता है और कृषि, समुद्री उत्पाद, कपड़ा, फार्मास्युटिकल, रसायन और कई इंजीनियरिंग उत्पादों में विविधता और प्रतिस्पर्धा के लाभ से भारत को महत्वपूर्ण निर्यातक बनने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

### भारत के वैश्विक व्यापार संबंध

11.31 वैश्वीकरण का यह युग व्यापार समझौतों के प्रसार और प्रतिस्पर्धी व्यापार ब्लॉकों के उद्भव के साथ आया है। ये रुझान हर व्यवसाय, हर उद्योग और हर देश को प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए इन परिवर्तनों के साथ तालमेल बिठाना दुनिया भर के नीति निर्माताओं के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। सरकारें बड़े पैमाने पर विविध विदेशी और आंतरिक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के विचार- जैसे कि शांति और स्थिरता को बढ़ावा देना, बाजार का आकार बढ़ाना और सबसे महत्वपूर्ण, अन्य देशों की प्रतिकूल व्यापार नीतियों के विरुद्ध स्वयं को सुरक्षित करना, से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहयोग का अनुसरण कर रही हैं।

11.32 भारत हमेशा एक खुले, न्यायसंगत, भविष्यवचनीय, गैर-भेदभावपूर्ण और नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए खड़ा रहा है। भारत क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाओं (आरटीए) को व्यापार उदारीकरण के समग्र उद्देश्य की दिशा में 'बिल्डिंग ब्लॉक' और बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली के पूरक के रूप में मानता है।

यह स्वीकार करते हुए कि क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्था (आरटीए) विश्व व्यापार में स्थायी रूप से विशिष्ट स्थान रखेगी, भारत ने पिछले दशक के शुरुआती हिस्से से अपने निर्यात बाजार का विस्तार करने के इरादे से अपने व्यापारिक भागीदारों/ब्लॉकों के साथ काम किया है और कुछ मामलों में व्यापक आर्थिक सहयोग समझौतों (सीईसीए) की ओर बढ़ने के लिए सैद्धांतिक समझौतों का निष्कर्ष निकालना शुरू किया है जिसमें माल, सेवाओं, निवेश से संबंधित मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) और आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करना शामिल है।

11.33 एफटीए के लिए आर्थिक तर्क भारत के अपने व्यापारिक भागीदारों के लिए निर्यात का विविधीकरण और विस्तार करना था, जिससे उचित वातावरण प्रदान किया जा सके और हमारे व्यापारिक भागीदारों में तुलनात्मक लाभ रखने वाले प्रतिस्पर्धी देशों की तुलना में कम लागत पर कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों (सहायक सामग्री/उत्पादों) तक पहुंच सरल की जा सके और मूल्य वर्धित घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके। भारत-दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ (आसियान), भारत-कोरिया और भारत-जापान से समझौतों के मामले में, यह भी एक भू-राजनीतिक रणनीति का हिस्सा था जो भारत की "पूर्व की ओर देखो नीति" के साथ अच्छी तरह से मेल खाता है।

11.34 भारत ने अब तक 13 मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) और 6 अधिमान्य व्यापार समझौता (पीटीए) किए हैं। सूची में सबसे नया भारत-संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (सीईपीए) है जिस पर 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे और आधिकारिक तौर पर यह 1 मई 2022 को प्रभावी हुआ था इसके साथ ही भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (INDAUS ECTA) है, जिस पर 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किए गए और यह 29 दिसंबर 2022 को प्रभावी हुआ था। इसके अतिरिक्त, भारत वर्तमान में अपने कुछ व्यापारिक भागीदारों के साथ मुक्त व्यापार समझौते की (एफटीए) वार्ताएं कर रहा है, इन एफटीए में - (i) भारत-यूके एफटीए, (ii) भारत-कनाडा सीईपीए/प्रारंभिक प्रगति व्यापार समझौता (ईपीटीए), (iii) भारत-यूरोपीय संघ एफटीए, उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा, भारत ने कुछ मौजूदा एफटीए, अर्थात् भारत-सिंगापर सीईसीए, भारत-दक्षिण कोरिया सीईपीए, और भारत-आसियान व्यापार समझौते की समीक्षा करने के लिए कार्रवाई शुरू की है और ऑस्ट्रेलिया के साथ सीईसीए के दायरे पर चर्चा शुरू की है, जैसा कि इंड-ऑस्ट्रेलिया ईसीटीए<sup>13</sup> के तहत परिकल्पित है। बॉक्स XI. 1 दुनिया भर में किए जा रहे एफटीए की संख्या में वृद्धि और व्यापारिक भागीदार के लिए उनकी उपयोगिता निर्धारित करने वाले विभिन्न कारकों पर चर्चा करता है।

### बॉक्स XI.1: मुक्त व्यापार समझौते

विश्व व्यापार संगठन के नियमों<sup>14</sup> के अनुसार एफटीए, या आरटीए, व्यापार और निवेश में किसी देश के लिए उसकी दक्षताओं का लाभ उठाने के लिए उपलब्ध आर्थिक साधन होते हैं। जून 2016 तक, सभी डब्ल्यूटीओ सदस्यों के पास अब कम से कम एक आरटीए प्रभावी होना चाहिए।

डब्ल्यूटीओ सदस्यों के साथ व्यापार समझौतों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है, आरटीए की 355 अधिसूचनाएं प्राप्त हैं (1 दिसंबर 2022 तक- स्रोत: डब्ल्यूटीओ वेबसाइट)। कई डब्ल्यूटीओ सदस्य नए आरटीए बनाने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जो अधिकतर द्विपक्षीय हैं। हालाँकि, हाल ही में दो से अधिक विश्व व्यापार संगठन सदस्यों के बीच बातचीत और नए समझौते हुए हैं, जैसे:

- चिली, कोलंबिया, मेक्सिको और पेरू के बीच प्रशांत गठबंधन (10 फरवरी 2014 को हस्ताक्षरित; 1 मई 2016 से प्रभावी);
- त्रिपक्षीय समझौता, जिसमें 'कॉमन मार्केट फॉर ईस्टर्न एंड साउथर्न अफ्रीका', 'ईस्ट अफ्रीका कम्युनिटी' और 'साउथर्न अफ्रीकन डेवलपमेंट कम्युनिटी' के साझा बाजार के साथ पक्षों को जोड़ा गया है (इसे 10 जून 2015 को प्रारंभ किया गया और विभिन्न सदस्यों द्वारा अलग-अलग तारीखों पर यह प्रभावी हुआ);
- व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (8 मार्च 2018 को हस्ताक्षरित; 31 अक्टूबर 2018 से प्रभावी हुआ);
- अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र (AFCFTA) (21 मार्च 2018 को हस्ताक्षरित और विभिन्न सदस्यों द्वारा अलग-अलग तारीखों से प्रभावी हुआ);
- आसियान सदस्यों और छह अन्य डब्ल्यूटीओ सदस्यों के बीच क्षेत्रीय व्यापक भागीदारी समझौता (आरसीईपी) (15 नवंबर 2020 को हस्ताक्षरित; 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हुआ)।

विश्व व्यापार संगठन में बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं में सीमित प्रगति एफटीए में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारणों में से एक है। विश्व व्यापार संगठन मंच पर बहुपक्षीय वार्ता की तुलना में एफटीए को व्यापारिक देशों द्वारा अनुकूल रूप से देखा जाता है क्योंकि इन पर बातचीत करने में सरलता होती है और ये भू-राजनीतिक विचारों में कारक को लचीलापन प्रदान करते हैं।

आरटीए का उद्देश्य वस्तुओं और सेवाओं पर शुल्क कम करना और व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से व्यापार भागीदारों के बीच सहयोग बढ़ाना, उपभोक्ताओं के लिए सस्ते उत्पाद और उत्पादकों के लिए निर्यात के बेहतर अवसर प्रदान करना है। आरटीए का अर्थव्यवस्था पर बड़ा प्रभाव भी होता है। उदाहरण के लिए, बेली और साथी (2019) ने पाया कि एफटीए प्रत्यक्ष घरेलू मूल्य वर्धित निर्यात के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंधित होते हैं, साथ ही वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में इनका फॉरवर्ड और बैकवर्ड पार्टिसिपेशन रहता है।

<sup>12</sup> भारत द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के व्यापार समझौतों को समझने के लिए, कृपया: [https://www.tpci.in/research\\_report/types-of-trade-agreements/](https://www.tpci.in/research_report/types-of-trade-agreements/) देखें

<sup>13</sup> RTAs, as per WTO rules, are any reciprocal trade agreement between two or more partners, not necessarily belonging to the same region.

टिनबर्गेन (1962) द्वारा विकसित कन्वेंशनल ग्रेविटी मॉडल के अनुसार, दो देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार उनके संबंधित आकार के अनुपात में होता है, जिसे उनके जीडीपी द्वारा मापा जाता है और यह व्यापार भौगोलिक दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो परिवहन लागत का प्रतिनिधि है। समय के साथ, व्यापार को प्रभावित करने में उनकी प्रासंगिकता का परीक्षण करने के लिए विनिमय दर, आय स्तर और शिफ्टिंग डिमांड पैटर्न जैसे अधिक चरों (वेरिएबल्स) , को मानक ग्रेविटी मॉडल में जोड़ा गया है (ओसाबुओहेन और साथी , 2019)।

जबकि एक एफटीए टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करके व्यापार बढ़ाने के लिए सक्षम वातावरण प्रदान करता है, किसी देश की व्यापार वृद्धि कई कारकों पर निर्भर करती है, जैसे:

- (क) एफटीए की विनिर्दिष्ट विशेषताएं जैसे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन (एमएफएन) टैरिफ<sup>15</sup> की तुलना में दी गई टैरिफ छूट की सीमा, किन उत्पादों पर उन्हें दिया जाता है और छूट किस प्रकार प्रदान की जाती है, अर्थात् , क्या छूट को लंबे समय से है या अल्प समय कब से लागू<sup>16</sup> करने पर सहमति दी जाती है।
- (ख) 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' (आरओओ) के संदर्भ में रियायतों की सीमा और गैर-टैरिफ बाधाओं (एनटीबी) को हटाना/सुधारना। जबकि टैरिफ बाधाओं को एफटीए में कम करने पर सहमति है, एनटीबी, जैसे सैनिटरी और फाइटोसैनेटिक उपाय, व्यापार के लिए तकनीकी बाधाएं, आकस्मिक व्यापार-सुरक्षात्मक उपाय आदि, व्यापारियों द्वारा एफटीए को कम उपयोगी बना सकते हैं।
- (ग) उत्पादों/सेवाओं की आपूर्ति बढ़ाने के लिए एक अर्थव्यवस्था की क्षमता जिसके लिए एफटीए ने एक उन्नत निर्यात स्थल प्रदान किया है। यह 'आपूर्ति-प्रतिक्रिया' कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला द्वारा निर्धारित की जाती है जो बड़े पैमाने पर एफटीए की सीमा से बाहर हैं। इनमें उत्पादन पहलुओं पर विभिन्न नीतियां, देश की भौतिक और संस्थागत अवसंरचना, और अर्थव्यवस्था के अल्पकालिक लचीलेपन को निर्धारित करने वाले अन्य तत्व शामिल हैं। दूसरे शब्दों में, आपूर्ति-प्रतिक्रिया व्यापार निर्माण की संभावना से नियंत्रित होती है जिसमें किसी एफटीए का एक सदस्य, एक उत्पाद का उत्पादन करने में तुलनात्मक लाभ प्राप्त करता है, अब इसे अपने एफटीए भागीदारों को बेचने में सक्षम हो जाता है क्योंकि व्यापार बाधाओं को हटा दिया गया है (विनर) , 1950)।
- (घ) एफटीए का प्रभाव आयात करने वाले बाजारों में आय वृद्धि और एक व्यापार समझौते में भागीदार देश को निर्यात की मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता पर भी निर्भर करेगा ताकि समझौते का लाभ उठाया जा सके।

इसके अतिरिक्त, सभी व्यापार एफटीए मार्ग के माध्यम से नहीं हो सकते हैं, विशेषकर यदि 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' (आरओओ) बोलिबल हैं या माल का व्यापार पहले से ही एमएफएन जीरो ड्यूटी हो रहा है। एफटीए का लाभ उठाने के लिए व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं द्वारा इनका अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए। और, ऐसा नहीं हो सकता है कि दो या दो से अधिक देशों के बीच एफटीए पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद व्यापार में अचानक से या महत्वपूर्ण वृद्धि होने लगे। व्यापार संतुलन केवल धीरे-धीरे परिवर्तित होगा और क्योंकि यह आंतरिक कारक पर आधारित रहता है इसलिए यह प्रत्येक भागीदार के पक्ष में भी नहीं हो सकता है, इनमें से कुछ ऊपर सूचीबद्ध किए गए हैं।

### संदर्भ

- बायर, एस.एल., वार्ड.वी. योतोव, और टी. जिलकिन। 2019. "ऑन द वाइडली डिफरिंग इफेक्ट्स ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स: लेसन फ्रॉम ट्वेन्टी इयर्स ऑफ ट्रेड इंटीग्रेशन" जर्नल ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स 116: 206-226।

<sup>14</sup> एमएफएन खंड एक देश द्वारा दूसरे देश को दी गई विशेष व्यापारिक स्थिति को संदर्भित करता है जो विश्व व्यापार संगठन के अन्य सभी सदस्यों पर लागू होता है।

<sup>15</sup> एफटीए में आम तौर पर नेज-इन अवधि होती है जिसमें मौजूदा व्यापार बाधाओं को समय के साथ समाप्त कर दिया जाता है। यह आम तौर पर इसलिए किया जाता है जिससे आयात करने वाले देश में उत्पादक आयात प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सकें। यह आमतौर पर एफटीए के अनुसमर्थन के 10 से 15 वर्षों के बाद होता है।

<sup>16</sup> किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए 'रूल्स ऑफ ओरिजिन' आवश्यक मानदंड होते हैं। उनका महत्व इस तथ्य से निकला है कि कई मामलों में शुल्क और प्रतिबंध आयात के स्रोत पर निर्भर करते हैं।

- ओसाबुहिएन, ई.एस., एफोबी, यू.आर., ओडेबियी, जे.टी., फयोमी, ओ.ओ., और सलामी, ए.ओ. (2019)। “पश्चिम अफ्रीका में द्विपक्षीय व्यापार प्रदर्शन: एक गुरुत्वाकर्षण मॉडल अनुमान,” अफ्रीकन डेवलपमेंट रिव्यू, 31(1), 1-14।
- टिनबर्गेन, जे. (1962)। “शेपिंग द वर्ल्ड इकोनामी; सजेसंस फॉर एन इंटरनेशनल इकोनामिक पॉलिसी”, न्यूयॉर्क: ट्वेंटीएथ सेंचुरी फंड।
- विनर, जे. (1950)। “द कस्टम यूनियन”, कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस, न्यूयॉर्क।

## चुनौतीपूर्ण अवधि में भुगतान संतुलन

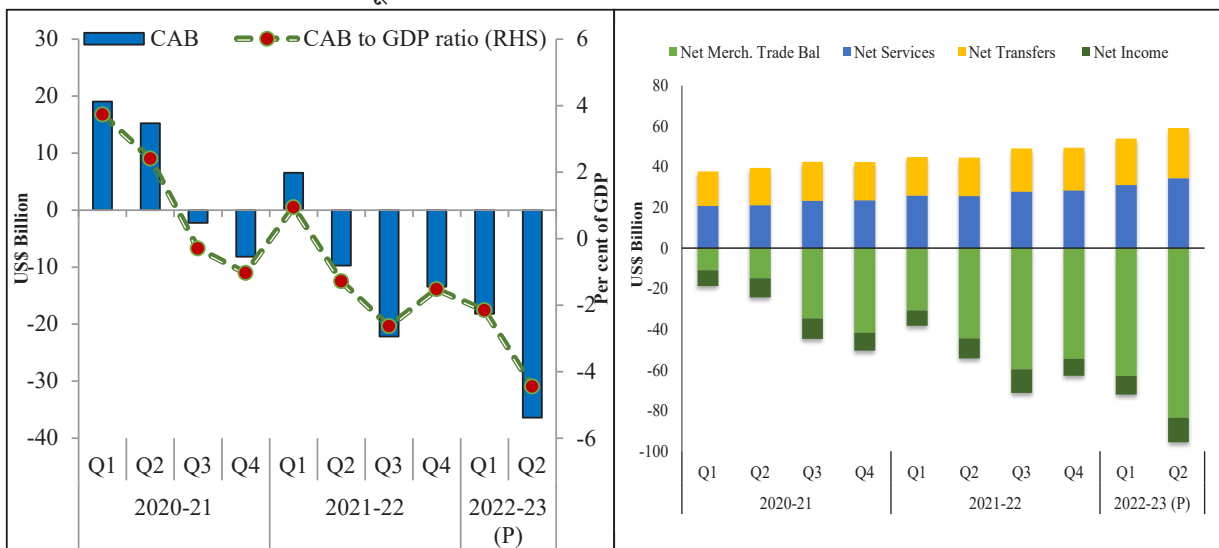
### चालू खाता शेष

11.35 भारत का बाह्य क्षेत्र भू-राजनीतिक विकास को दर्शाते हुए काफी वैश्विक विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा है, जैसा कि ऊपर के परिचय खंड में बताया गया है। वित्त वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में भारत के चालू खाता शेष (CAB) में 36.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 4.4 प्रतिशत) का घाटा दर्ज किया गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 9.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.3 प्रतिशत) था। FY23 की दूसरी तिमाही में चालू खाता घाटे (CAD) का बढ़ना मुख्य रूप से 83.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के उच्च पण्य व्यापार घाटे और निवल निवेश आय में निर्गम के कारण था। अप्रैल-सितंबर 2022 (H1 FY 23) की अवधि के लिए, भारत ने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 3.3 प्रतिशत का चालू खाता घाटा (CAD) दर्ज किया, जो वित्त वर्ष 2021-22 की पहली छमाही में 0.2 प्रतिशत की तुलना में पण्य व्यापार घाटे में वृद्धि के कारण पर था। हालांकि, चयनित देशों के लिए चालू खाता शेष (सीएवी) की स्थिति के साथ तुलना से पता चलता है कि भारत का चालू खाता घाटा (CAD) मामूली और प्रबंधनीय सीमा के भीतर है।

चित्र XI.7: चालू खाता शेष (CAB): परिमाण और संरचना

क) चालू खाता शेष और सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में चालू खाता शेष

ख) चालू खाता शेष की संरचना

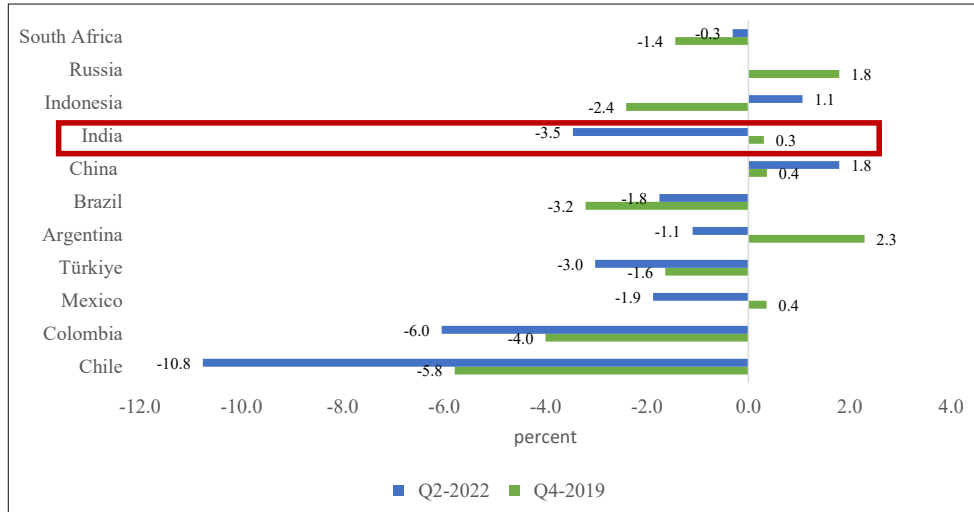


स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

P: अनंतिम



चित्र XI.8: सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में चालू खाता शेष: भारत बनाम चुनिंदा देश

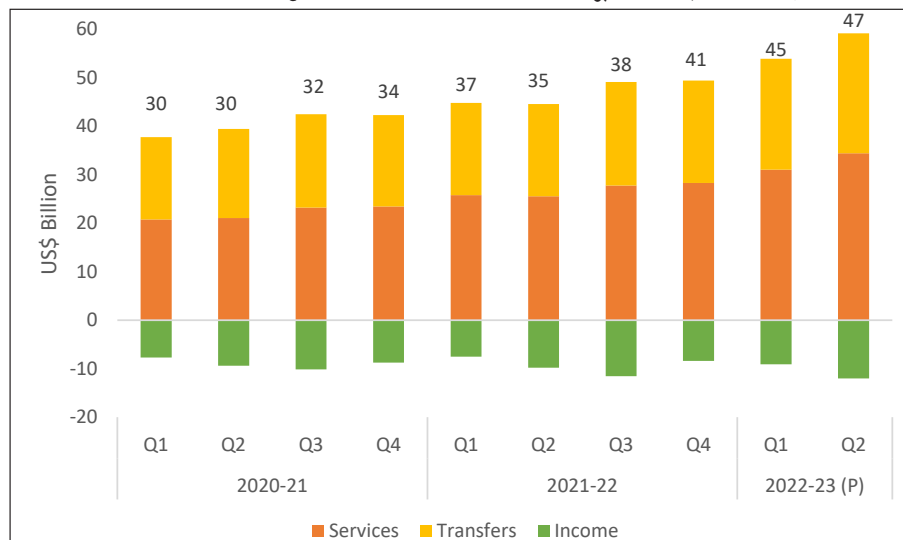


स्रोत: ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) इकोनॉमिक आउटलुक 112 डाटाबेस

### व्यापार की अदृश्य मदें

11.36 शुद्ध सेवा प्राप्तियां वित्त वर्ष 22 की पहली छमाही में 51.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में 65.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई, जिसका मुख्य कारण मजबूत कंप्यूटर और व्यावसायिक सेवा प्राप्तियां हैं। इसी तरह, निवल प्राइवेट ट्रांसफर रिसिप्ट, जो मुख्य रूप से विदेशों में कार्यरत भारतीयों द्वारा धन-प्रेषण का प्रतिनिधित्व करती हैं, वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही में 48.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जबकि एक साल पहले इसी अवधि के दौरान उनका स्तर 38.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। कच्चे तेल की कीमतों में तेज वृद्धि और भारतीय रुपये के अवमूल्यन ने भारत में धन-प्रेषण प्रवाह को बढ़ावा दिया है। निवल सेवाओं के निर्यात और धन-प्रेषण ने अदृश्य मद व्यापार खाते के अधिशेष में योगदान दिया है, जिसने पण्य व्यापार घाटे को कम किया है।

चित्र XI.9: व्यापार की निवल अदृश्य मदों की संरचना: मजबूत सेवाएं और बड़ी मात्रा में धन-प्रेषण

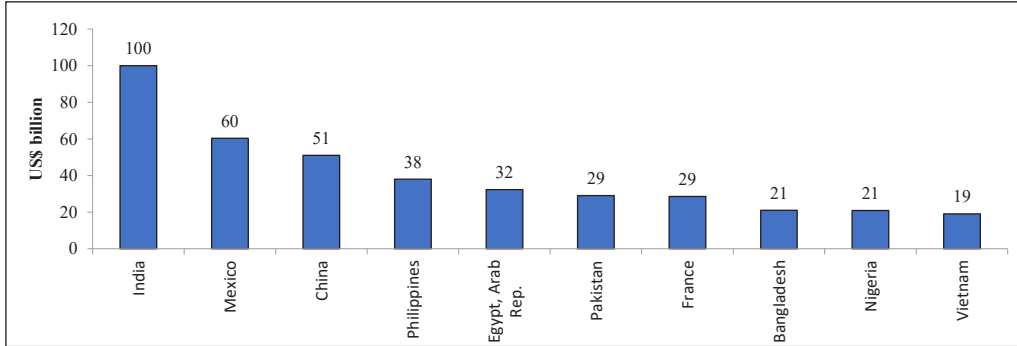


स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक P: अनंतिम

11.37 विदेशों में कार्यरत भारतीय द्वारा 'धन-प्रेषण' सेवा निर्यात के बाद विदेशी वित्तपोषण का दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत है, जो चालू खाता घाटे (CAD) को कम करने में योगदान देता है और हमेशा भुगतान संतुलन (BoP) का एक स्थिर घटक रहा है। भारत की प्रवासी आबादी सबसे बड़ी है। विश्व बैंक<sup>17</sup> के अनुसार वर्ष 2022 में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के प्रत्याशित धन-प्रेषण स्तर के साथ भारत शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश

रहा है। भारतीय प्रवासियों के प्रमुख गंतव्य में क्रमिक संरचनात्मक बदलाव से धन-प्रेषण को लाभ हुआ है, ऐसा बड़े पैमाने पर खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) देशों में कम-कुशल व अनौपचारिक रोजगार के स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और पूर्वी एशिया (सिंगापर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड)<sup>18</sup> जैसे उच्च आय वाले देशों में उच्च-कुशल रोजगार का बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के कारण हुआ है।

चित्र XI.10: 2022 के दौरान विश्व के शीर्ष धन-प्रेषण प्राप्तकर्ता (अनुमानित)



स्रोत: विश्व बैंक

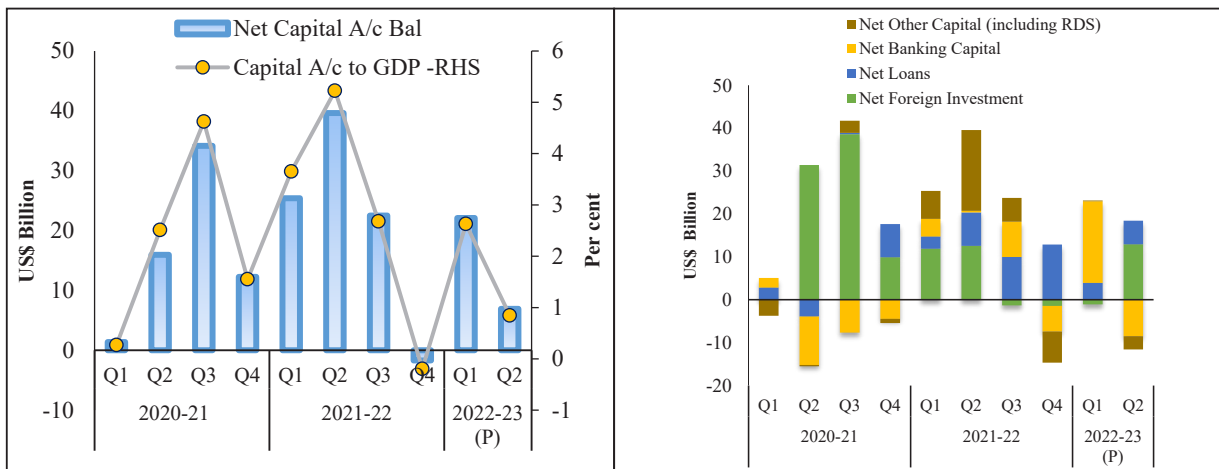
### पूँजीगत खाता शेष

11.38 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) से मिलकर विदेशी निवेश, पूँजीगत खाते का सबसे बड़ा घटक है। निवल पूँजीगतगत प्रवाह वित्तवर्ष 22 की पहली माही H1 में अमेरिकी डॉलर 65.0 बिलियन से घटकर वित्तवर्ष 23 की पहली माही H1 में अमेरिकी डॉलर 29.0 बिलियन हो गया<sup>19</sup>, ऐसा मुख्य रूप से वित्तवर्ष 23 की पहली माही (Q1FY23) में 14.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) के बहिर्गमन के कारण हुआ। वित्तवर्ष 23 की पहली छमायी (H1FY23) में अमेरिकी डॉलर 20.0 बिलियन का निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह वित्तवर्ष 22 की पहली माही (H1FY22) में अमेरिकी डॉलर 20.3 बिलियन के साथ तुलनीय था।

चित्र XI.11: पूँजीगत खाता शेष: परिणाम एवम संरचना

(क) पूँजीगत लेखा शेष: वैश्विक अनिश्चितता के बीच कम होता सरप्लस

(ख) पूँजीगत लेखा शेष का संघटन



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक P: अनंतिम

11.39 अप्रैल-सितंबर 2022 के दौरान, एक साल पहले के 42.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में सकल एफडीआई प्रवाह 39.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ने विदेशी प्रत्यक्ष

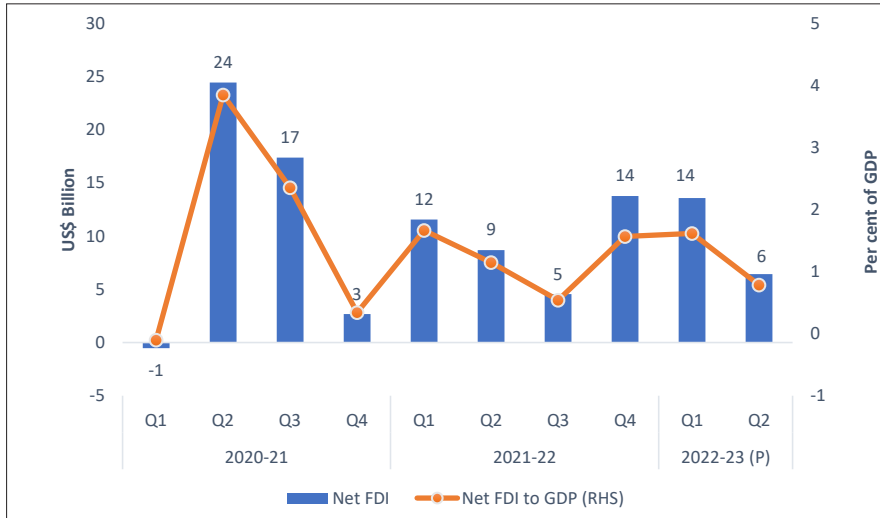
<sup>17</sup> वर्ल्ड बैंक, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 37, नवंबर 2022

<sup>18</sup> वर्ष 2020-21 के लिए धन-प्रेषण (रेमिटेंस) पर सर्वेक्षण का पांचवां दौर, भारतीय रिजर्व बैंक।

<sup>19</sup> इसमें वित्तवर्ष 22 की दूसरी तिमाही (Q2FY22) में US\$ 17.9 बिलियन के विशेष आहरण अधिकार (SDR) का अतिरिक्त आवंटन शामिल था।

निवेश इक्विटी प्रवाह का उच्चतम भाग(23.4 प्रतिशत) आकर्षित किया, इसके बाद सेवाओं (15.4 प्रतिशत) और ट्रेडिंग (12.2 प्रतिशत) का स्थान रहा। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह के संदर्भ में, सिंगापर 37.0 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ शीर्ष निवेश करने वाला देश था, इसके बाद मॉरीशस (12.1 प्रतिशत), यूएई (11.0 प्रतिशत) और यूएसए (10.0 प्रतिशत) का स्थान था।

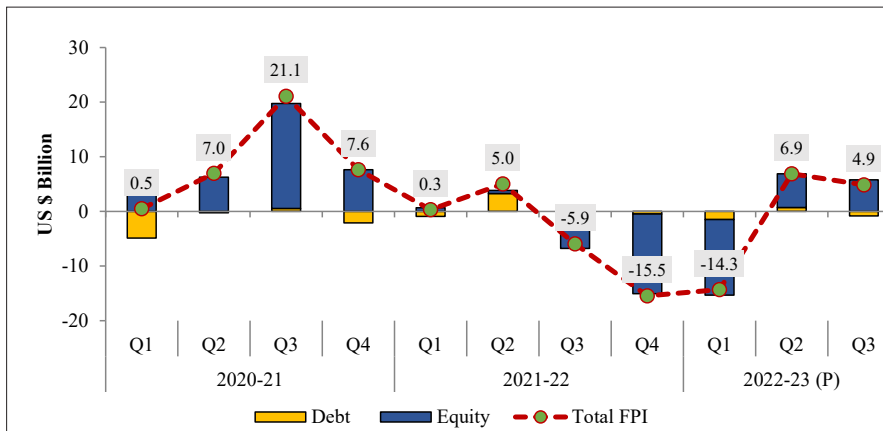
चित्र XI.12: निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक P: अनंतिम

11.40 रूस-यूक्रेन संघर्ष और संयुक्त राज्य अमेरिका (फेडरल रिजर्व) द्वारा आक्रामक मौद्रिक नीति को कड़ा करने के नतीजों ने वैश्विक वित्तीय बाजार में अस्थिरता को बढ़ा दिया, जिससे वित्तवर्ष 23 की पहली तिमाही (Q1) में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा निवल आउटफ्लो हुआ। हालाँकि, FPI प्रवाह Q2FY23 में सकारात्मक हो गया, कुल मिलाकर, पोर्टफोलियो निवेश ने अप्रैल-दिसंबर 2022 के दौरान 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध बहिर्वाह दर्ज किया, जबकि एक साल पहले 0.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बहिर्वाह हुआ था।

चित्र XI.13: निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश



स्रोत: नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) P: अनंतिम

11.41 वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही (H1FY23) में पूंजी प्रवाह के अन्य रूपों में, बैंकिंग पूंजीगत प्रवाह ने वित्त वर्ष 2022 की इसी अवधि के दौरान 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में 10.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का उच्च निवल प्रवाह सूचित हुआ। वैश्विक तरलता की स्थिति कड़ी होने के कारण, वित्त वर्ष 23 की पहली छमाही (H1FY23) के दौरान अल्पकालिक व्यापार ऋण (ट्रेड-क्रेडिट) की मांग बढ़ी, जिसके परिणामस्वरूप 10.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उच्च निवल अल्पकालिक ऋण प्राप्ति हुई। इसके अलावा, नए संवितरणों की तुलना में अधिक चुकौती के साथ, भारत में विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) ने वित्त वर्ष

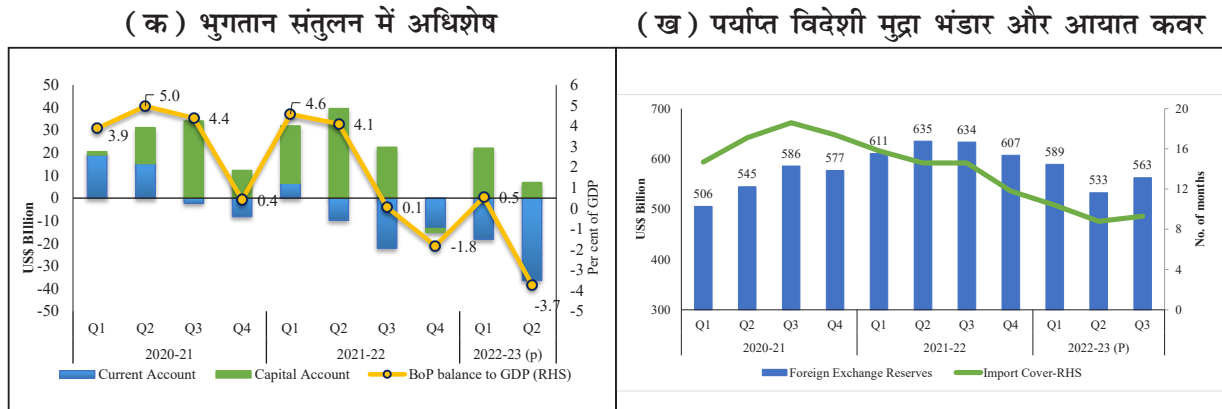
23 की पहली छमाही (H1FY23) में 3.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह दर्ज किया, जबकि एक साल पहले 5.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्प्रवाह हुआ था।

### भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा भंडार

11.42 कुल मिलाकर, प्रतिकूल वैश्विक आर्थिक स्थिति ने 2022 में भारत के भुगतान संतुलन (BoP) को दबाव में रखा। जबकि तेल की कीमतों में तेज वृद्धि का प्रभाव चालू खाता घाटा (CAD) के बढ़ने में देखा जा सकता था, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा नीति को कड़ा करने और अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) का बहिर्वाह हुआ। परिणामस्वरूप, चूंकि 'निवल वित्तीय प्रवाह' चालू खाते के घाटे से कम हो गया, इसलिए भुगतान संतुलन (BoP) के आधार पर विदेशी मुद्रा भंडार में वित्तवर्ष 23 की पहली छमाई (H1FY23) में 25.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी आई, जो वित्तवर्ष 22 की पहली छमाई (H1FY22) में अमेरिकी डॉलर 63.1 बिलियन की अभिवृद्धि के विपरीत थी। लेकिन भारी निवेश मूल्यांकन हानियों (48.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर) ने इस अवधि के दौरान नोमिनल दर से 74.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भंडार में निवल कमी की।

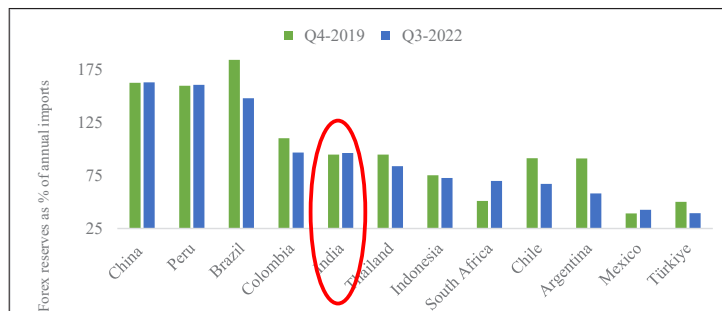
11.43 सितंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 532.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसमें 8.8 महीने का आयात शामिल था। 9.3 महीने के आयात को सम्मिलित करते हुए दिसंबर 2022 के अंत तक विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। आईएमएफ द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2022 के अंत तक, भारत दुनिया का छठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार धारक था। जैसा कि ग्राफ से देखा जा सकता है, अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में महामारी से पहले के स्तर के बाद से विदेशी मुद्रा भंडार के इम्पोर्ट-कवर में गिरावट आई है; हालाँकि, भारत ने वर्ष 2019 को चौथी तिमाही के 95 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में 96.5 प्रतिशत तक की वृद्धि दर्ज की। बॉक्स XI.2 में देश के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार का गठन करने वाले शास्त्र के कुछ पहलुओं पर चर्चा की गयी है।

चित्र XI.14: समग्र भुगतान संतुलन शेष और विदेशी मुद्रा भंडार



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक P: अनंतिम

चित्र XI.15: भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता (वार्षिक आयात के प्रतिशत के रूप में): एक क्रॉस-कंट्री परिप्रेक्ष्य



स्रोत: आईएमएफ (विदेशी मुद्रा भंडार) और विश्व व्यापार संगठन (आयात डेटा के लिए)

## बॉक्स XI.2 विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता

विदेशी मुद्रा भंडार (FER) के पर्याप्त स्तर का आकलन कैसे करें? क्या कुछ अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क या मूल नियम हैं जो मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकते हैं? वे कौन से कारक हैं जिन पर देश को “पर्याप्तता” की अपनी सीमा निर्धारित करते समय विचार करना चाहिए? मात्र उपलब्धता की तुलना में इस तरह के भंडार की तरलता को कैसे सुनिश्चित किया जाए? यह बॉक्स प्रासंगिक शास्त्र अध्ययन के अकादमिक दृष्टिकोण संबंधी सवालों के जवाब देने का प्रयास करता है।

विभिन्न उद्देश्यों के लिए विदेशी मुद्रा भंडार (FER) की आवश्यकता होती है, जैसे कि - आयात के लिए ऋण देना; विदेशी दायित्वों का समय पर निर्वहन करना, विनिमय दर को निश्चित सीमा के भीतर बनाए रखना, या विनिमय दर को किसी निश्चित स्तर पर बनाए रखना यदि देश निश्चित विनिमय दर प्रणाली का पालन करता है; तरलता बनाए रखना और उन स्थितियों में आर्थिक परिवर्तनों को सहने के लिए समय देना, जहां उधार लेने के लिए पहुंच कम होती है या बहुत महंगी होती है। भंडार के संचय के पीछे के कारक का विकास वर्षों में हुआ है: प्रथमतः 2000 के दशक की शुरुआत तक इनका उद्देश्य निवारण करना था, इसके उपरान्त मौद्रिक और विनिमय दर नीतियों में भी इसका लक्ष्य रखा जाने लगा (अर्सलान यवुज, और साथी 2019)। तदनुसार, 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से कई देशों के एफईआर में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है।

तालिका: सोने को छोड़कर कुल विदेशी मुद्रा भंडार ( बिलियन अमेरिकी डॉलर में )

	2005	2008	2019	2020	2021	नवंबर-2022	2008 की तुलना में 2021 में परिवर्तन का प्रतिशत
रूसी संघ	175.9	411.8	443.9	457.0	497.6	567.3	20.8
भारत	131.9	247.4	432.4	549.1	594.4	555.3	140.3
ब्राजील	53.3	192.8	353.6	351.5	354.6	331.5	83.9
संयुक्त राज्य अमेरिका	54.1	66.6	118.4	133.9	240.2	237.8	260.7
यूनाइटेड किंगडम	54.0	56.1	158.4	161.2	176.0	204.1	213.7
इंडोनेशिया	33.1	49.6	125.3	131.1	140.3	134.0	182.9
दक्षिण अफ्रीका	18.6	30.6	48.9	47.4	50.3	60.0	64.4
ऑस्ट्रेलिया	41.9	30.7	55.6	39.2	53.8	57.9	75.2
विश्व	<b>4395.0</b>	<b>7418.2</b>	<b>12195.3</b>	<b>13122.5</b>	<b>13944.7</b>	<b>11598.6*</b>	<b>88.0</b>

स्रोत: अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सांख्यिकी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

\*Figure as of Sept 2022

यहां विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता पर विचार-विमर्श किया गया है। परंपरागत रूप से, विदेशी मुद्रा भंडार की पर्याप्तता का उपाय तीन प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जैसे विदेशी मुद्राभंडार और आयात का अनुपात रखने, मौद्रिक समुच्चय रखने, और विदेशी ऋण चुकाने के लिए (आईएमएफ, 2000)। भंडार की पर्याप्तता निर्धारण के पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार, मूल सरल नियम तीन महीने का आयात या अल्पकालिक ऋण के लिए संपूर्ण कवर रखना है। पूर्व के संबंध में, दो या छह (आईएमएफ, 2011) के स्थान पर तीन महीने पर्याप्त का कवरेज होना चाहिए या नहीं, इसके लिए बहुत कम अनुभवजन्य साक्ष्य प्राप्त है। परवर्ती कथन गाइडोटी-ग्रीनस्पैन-आईएमएफ नियम पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि देश के भंडार को अल्पकालिक विदेशी ऋण (एक वर्ष या उससे कम परिपक्वता) के बराबर होना चाहिए, जो विदेशी मुद्रा भंडार और अल्पकालिक ऋण के अनुपात का मान 1(एक) रखने का सुझाव देता है। तर्क यह है कि अल्पावधि विदेशी पूंजी की वापसी से निपटने के लिए देशों के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार होना चाहिए। इसके साथ विदेशी-मुद्रा-भंडार के मुद्रा आधारित संकेतक भी हैं, जो देश से निवासी आधारित

पूँजी का बड़े पैमाने पर पलायन रोकने के उपाय की क्षमता प्रदान करते हैं। उपयोग किए जाने वाले संकेतक 'ब्रॉड मनी' के भंडार का अनुपात या 'बेस मनी' के लिए भंडार का अनुपात हैं, जो निश्चित विनिमय दर व्यवस्थाओं के अंतर्गत विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्तता का आकलन करने में सहायता करते हैं। इन सूचकों में से प्रत्येक, अपने आप में, अर्थव्यवस्था के लिए विदेशी मुद्रा भंडार (FER) की आवश्यकताओं का आकलन करने में पर्याप्त नहीं हो सकता और अलग-अलग उद्देश्यों के लिए अलग-अलग उपायों का उपयोग किया जा सकता है।

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) (SM/00/65, 3/23/2000) ने जोखिम के स्रोत के रूप में अल्पकालिक ऋण के महत्व को पहचाना पतन्तु निर्भरता के लिए एक ही संकेतक पर अत्यधिक निर्भर रहने के प्रति सावधान किया और विदेशी मुद्रा भंडार के लिए अल्पकालिक मांग के विभिन्न संभावित स्रोतों पर विचार करने की आवश्यकता की ओर संकेत किया। इसके अलावा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) (SM/01/311, 10/16/2001) ने भुगतान संतुलन के तनाव-परीक्षण के साथ संकेतक-आधारित विश्लेषणों को पूरा करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया है। इसके अतिरिक्त, विदेशी देनदारियों (ऋण और इक्विटी) के साथ-साथ चालू खाता चर (निर्यात आय) से उत्पन्न होने वाले जोखिम के स्रोतों को पकड़ने के लिए अनुकूलित रिस्क बेस्ड ब्रॉड बेस्ड मेट्रिक्स और संभावित बड़े पैमाने पर पूँजी का पलायन रोकने के कुछ उपाय (ब्रॉड मनी) (आईएमएफ, 2011) तैयार किए गए हैं। इकनोमिक शॉक से निपटने के लिए उपलब्ध कुल संसाधनों के संदर्भ में पर्याप्तता पर विचार किया जाना चाहिए जोकि आरक्षित परिसंपत्तियों की भुगतान क्षमता पर आधारित परिभाषा की तुलना में एक व्यापक अवधारणा है। जबकि विदेशी मुद्रा भंडार वित्तीय-संकट की स्थितियों को रोकने और उनके प्रभाव को कम करने दोनों के लिए आवश्यक होता है, उन्हें धारण करने में लागत लगती है और ये ह्रासमान प्रतिफल देते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार रखने के लिए एक अर्थव्यवस्था द्वारा वहन की जाने वाली लागत में 'अवसर लागत' (घरेलू और विदेशी उधार दरों के बीच अंतर के रूप में) और डेनोमिनेटिड एफईआर के मूल्य में कमी के कारण होने वाला नुकसान शामिल है। रॉड्रिक (2006) ने विदेशी मुद्रा भंडार की सामाजिक लागत की जांच की है और कहा है कि अधिकांश विकासशील देशों की आय की हानि सकल घरेलू उत्पाद के एक प्रतिशत के करीब होती है।

फुकुदा और कोन (2010) विदेशी मुद्रा भंडार संचय के व्यापक आर्थिक प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं और इस बात का प्रमाण पाते हैं कि एफईआर में वृद्धि से विदेशी ऋण बकाया बढ़ जाता है किंतु ऋण परिपक्वता कम हो जाती है। इसके अलावा, लंबे समय में, खपत में गिरावट आती है और निर्यात को बढ़ावा मिलता है जोकि गैर-व्यापार योग्य क्षेत्र से व्यापार योग्य क्षेत्र में उच्च निवेश और विकास के माध्यम से बदलाव को प्रोत्साहित करके होता है। इसके अलावा, 'विदेशी मुद्रा भंडार' विनिमय दर प्रभावों और नैतिक जोखिम व प्रोत्साहन प्रभाव (चिट्टू, 2016) के कारण मुद्रास्फीतिकारी हो सकते हैं (लिन, और साथी 2009)। इसलिए, विदेशी मुद्रा भंडार रखने के लाभों, लागतों और इसके प्रभावों पर विचार करते हुए देश को अपने विदेशी मुद्रा भंडार और मुद्रा संरचना की इष्टतम मात्रा रखनी चाहिए। रोलओवर संकट के संदर्भ में अचानक आर्थिक ठहराव की बाधा को देखते हुए भंडार का इष्टतम स्तर सरकार को प्रतिनिधि उपभोक्ता के कल्याण को अधिकतम करने का अधिकार देता है। दूसरी ओर, की-करेंसी और व्यापार इनवाँइस की मुद्रा के साथ डोमेस्टिक करेंसी(घरेलू मुद्रा) का सहसंबंध (आईटीओ, 2019); व्यापार प्रवाह (व्यापार इनवाँइस), वित्तीय प्रवाह (मुद्रा में ऋण सेवा भुगतान का हिस्सा), करेंसी पेग्स (आइचेंग्रीन, 2000) विदेशी मुद्रा भंडार की मुद्रा संरचना को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। इसके अलावा, वित्तीय विवरण- वैल्यू एट रिस्क (VaR) दृष्टिकोण का उपयोग भी इष्टतम विदेशी मुद्रा पोर्टफोलियो (हंग और साथी, 2008) को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। जैसा कि ऊपर संक्षेप में समीक्षा की गई है, विदेशी मुद्रा भंडार पर्याप्तता के समृद्ध साहित्य संभावित रूप से नीतिगत विकल्पों के बेहतर चयन और अनुकूल परिणामों के लिए तैयार है।

### संदर्भ

- अर्सलन, यावुज एंड कैट्टू, कार्लोस (2019), "द साइज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स", बीआईएस पेपर नंबर 104
- चिउ, जे-एस, हंग, जे-सी, और हसेउ, एम-एम। (2008), "अ वीएआर इन्वेस्टिगेशन ऑफ करेंसी कंपोजिशन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स", इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स, 21, 76-92।
- चीटू एल (2016), "रिजर्व एक्यूलेशन, इन्फ्लेशन एंड मोरल हार्जर्ड: एविडेंस फ्रॉम नेचुरल एक्सपेरिमेंट", वर्किंग पेपर सीरीज, नंबर 1880, यूरोपीयन सेंट्रल बैंक, जनवरी।

- आइचेनग्रीन, बी एंड मैथीसन, डी.जे. (2000), “द करेंसी कंपोजिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स: रेट्रोस्पेक्ट एंड प्रॉस्पेक्ट्स”, आईएमएफ वर्किंग पेपर्स, WP/00/131।
- फुकुदा, एस. आई. एंड कोना वाई (2010), “मैक्रोइकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एक्टिवेशन थ्योरी एंड इंटरनेशनल एविडेंस”; एडीबीआई वर्किंग पेपर सीरीज, नंबर 197, फरवरी।
- आईएमएफ (2000), “डेट एंड रिजर्व रिलेटेड इंडिकेटर्स ऑफ एक्सटर्नल वूलनेरेबिलिटी”, पॉलिसी एंड रिव्यू डिपार्टमेंट”, 23 मार्च।
- आईएमएफ (2011), “अस्सेसिंग रिजर्व एडेक्वेसी” मॉनेटरी एंड कैपिटल मार्केट, रिसर्च एंड स्ट्रेटजी, पॉलिसी एंड रिव्यू डिपार्टमेंट
- आईटीओ, एच एंड मैककौली, आर.एन. (2019), “द करेंसी कंपोजिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स”, मॉनिटरी एंड इकोनॉमिक डिपार्टमेंट, बीआईएस वर्किंग पेपर्स, नंबर 828, दिसंबर।
- जीन, ओ एंड रेनसीयर, आर (2006), “द ऑप्टिमल लेवल ऑफ इंटरनेशनल रिजर्व्स फॉर इमर्जिंग मार्केट कंट्रीज: फॉर्मूला एंड एप्लीकेशन”, IMF वर्किंग पेपर्स, WP/06/229।
- लिन, एम.वाई, एंड वांग, जे.एस. (2009), “फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड इन्फ्लेशन : एन एम्पिरिकल स्टडी ऑफ फाइव ईस्ट एशियन इकोनॉमीज”: , द एम्पिरिकल इकोनॉमिक्स लेटर, 8(5): मई।
- रोड्रिग, डी. (2006), “द सोशल कॉस्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स”, इंटरनेशनल इकोनॉमिक जर्नल, 20, 253-266।

## वैश्विक विकास के साथ घटती बढ़ती विनिमय दर

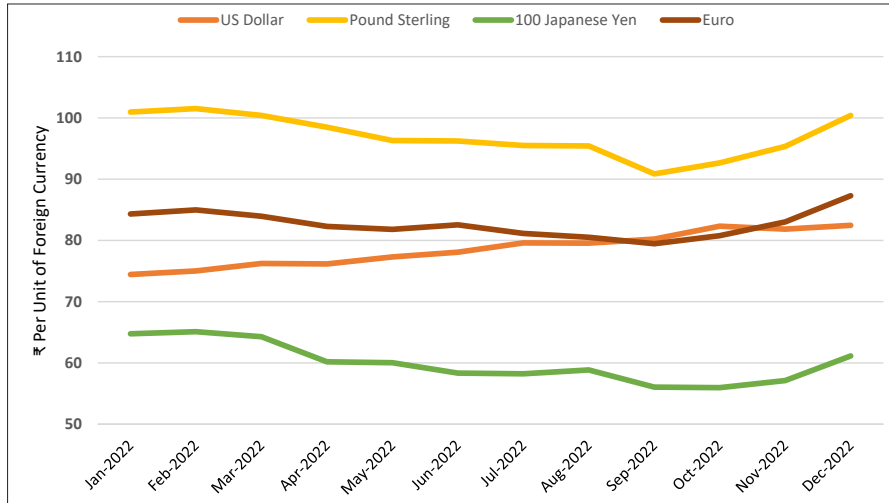
11.44 भारतीय रुपये की विनिमय दर बाजार-निर्धारित है, क्योंकि विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई का हस्तक्षेप मुख्य रूप से अत्यधिक अस्थिरता की स्थिति को नियंत्रित करना होता है। वित्तीय वर्ष के आधार पर, अर्थात् अप्रैल से दिसंबर 2022 तक, भारतीय रुपये में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8.3 प्रतिशत<sup>20</sup> की गिरावट आई है। इसी अवधि में, यूएस डॉलर इंडेक्स<sup>21</sup> के संदर्भ में अमेरिकी डॉलर में 4.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। ऐसा कैलेंडर वर्ष के आधार पर भी हुआ है, अर्थात् जनवरी से दिसंबर 2022 तक, भारतीय रूपए में 10.8 प्रतिशत की गिरावट आई है जबकि अमेरिकी डॉलर में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अमेरिकी डॉलर की नोमिनल इफेक्टिव विनिमय दर (27 अर्थव्यवस्था) 2022 में दिसंबर तक 7.8 प्रतिशत बढ़ी। जबकि भारत की एनईईआर (64 अर्थव्यवस्था) में 4.8 प्रतिशत की गिरावट आई है। दूसरे शब्दों में, ऐसा नहीं है कि भारतीय रुपया कमजोर हुआ है, बल्कि अमेरिकी डॉलर मजबूत हुआ है। उस टिप्पणी के विरुद्ध कितने ही ट्वीट लिखे जायें, यह एक सच्चाई है। भारतीय रुपये की तुलना में कई अन्य मुद्राओं का अमेरिकी डॉलर के मुकाबले और भी अधिक मूल्यहास हुआ (अध्याय I का चित्र देखें)। इस प्रकार, वर्तमान भू-राजनीतिक संकट की शुरुआत के बाद से वर्ष के दौरान अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के विदेशी मूल्य में बहुत व्यवस्थित गति देखी गई है।

11.45 इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर को छोड़कर चुनिंदा प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले भारतीय रुपये के दाम बढ़े हैं। पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले भारतीय रुपये की औसत विनिमय दर अप्रैल-दिसंबर 2022 में अप्रैल-दिसंबर 2021 की तुलना में 6.7 प्रतिशत बढ़ी। जापानी येन के संबंध में बढ़त की यह दर 14.5 प्रतिशत थी और यूरो के मुकाबले 6.4 प्रतिशत।

20 अप्रैल 2022 की तुलना में दिसंबर 2022 में मासिक औसत विनिमय दर में परिवर्तन।

21 यू.एस. डॉलर इंडेक्स (यूएस+एक्स) विदेशी मुद्राओं के एक सेट के सापेक्ष यू.एस. डॉलर के मूल्य का माप है। ये मुद्राएँ हैं: यूरो, स्विस फ्रैंक, जापानी येन, कैंनेडियन डॉलर, ब्रिटिश पाउंड और स्वीडिश क्रोना।

चित्र XI.16: प्रमुख मुद्राओं की तुलना में भारतीय रुपये की विनिमय दर



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

नोट: जापानी येन की विनिमय दर रुपये प्रति 100 येन में है।

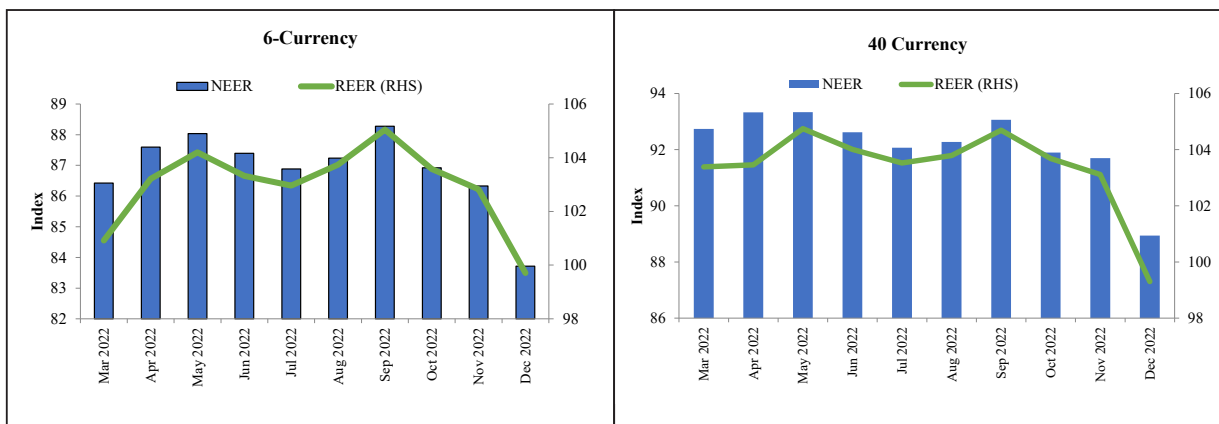
11.46 विनिमय दर के उतार-चढ़ाव की क्रॉस-कंट्री तुलना प्रायः मुद्रास्फीति-समायोजन आधार पर की जाती है या जिसे रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट (REER) कहा जाता है। वित्तीय वर्ष के आधार पर, अर्थात अप्रैल 2022 और दिसम्बर 2022 के मध्य, भारतीय रुपये में क्रमशः 6-मुद्रा और 40-मुद्रा व्यापार-भारित सूचकांकों के संदर्भ में 3.4 प्रतिशत और 4.0 प्रतिशत की गिरावट हुई। इस प्रकार, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) में वैश्विक स्पिलओवर प्रभाव के सामने भी भारतीय रुपये में मामूली मूल्यहास देखा गया छ

11.47 6-मुद्रा नोमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट (NEER) (ट्रेड -वेटेड) के संदर्भ में, अप्रैल 2022 की तुलना में दिसम्बर 2022 में रुपये में 0.4 प्रतिशत की गिरावट हुई। इसी तरह, अप्रैल 2022 की तुलना में दिसम्बर 2022 में 40-मुद्रा नोमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट (NEER) (ट्रेड -वेटेड) के संदर्भ में रुपये में 0.7 प्रतिशत की गिरावट हुई।<sup>22</sup>

चित्र XI.17: 6-मुद्रा और 40-मुद्रा नोमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ( एनईईआर) और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ( आरईईआर) (ट्रेड -वेटेड) के सूचकांक में उतार-चढ़ाव (आधार वर्ष 2015-16 = 100)

(क): 6- मुद्राओं के व्यापार पर आधारित

(ख): 40- मुद्राओं में व्यापार पर आधारित



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक P: अनंतिम

22 एनईईआर और आरईईआर सूचकांक विदेशी प्रतिस्पर्धात्मकता के संकेतक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। एनईईआर विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में घरेलू मुद्रा के बाई-लेटरल नोमिनल एक्सचेंज रेट का भारित औसत है। यह भार पिछले तीन वर्षों के दौरान 6 व 40 मुद्राओं द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए देशों/क्षेत्रों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार (निर्यात और आयात) के औसत पर आधारित है। आरईईआर, जिसे घरेलू और विदेशों के बीच सापेक्ष मूल्य अंतर के लिए समायोजित नोमिनल एक्सचेंज रेट के भारित औसत के रूप में परिभाषित किया गया है, पीपीपी परिकल्पना से संबंधित है।



## अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति: भारत की ठोस वित्तीय स्थिति का प्रतिबिम्ब

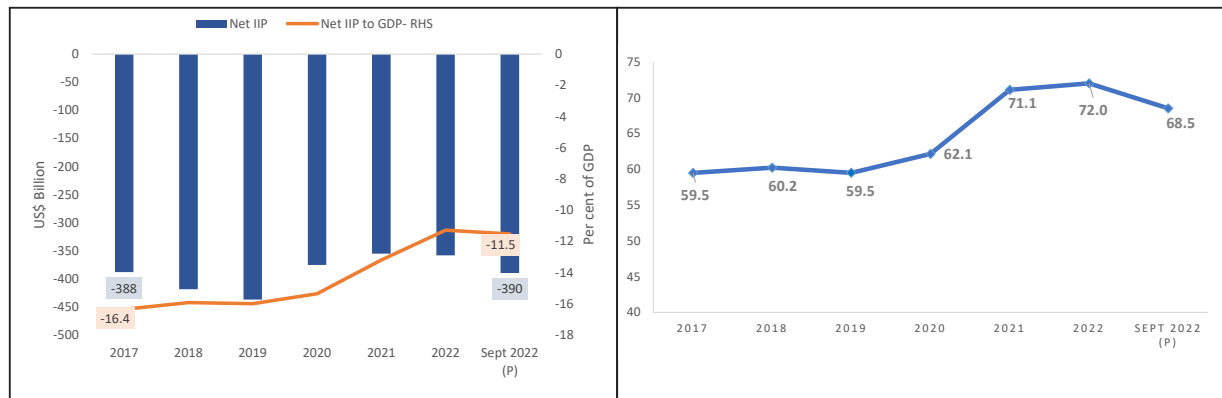
11.48 अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (IIP) एक सांख्यिकीय विवरण है जो, समय के साथ निम्नलिखित की संरचना को दर्शाता है (क) देश के निवासियों की वित्तीय संपत्ति का मूल्य जो अनिवासियों पर धन वापसी का दावा है तथा गोल्ड बुलियन के रूप में आरक्षित संपत्ति है; और (ख) जो देश के निवासियों की अनिवासियों के प्रति देनदारियां हैं। अर्थव्यवस्था की विदेशी वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों के बीच का अंतर अर्थव्यवस्था की निवल अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (IIP) का मान होता है, जो सकारात्मक या नकारात्मक<sup>23</sup> हो सकती है। निवल आईआईपी स्थिति यह निर्धारित करती है कि क्या कोई देश विदेशी संपत्ति और देनदारियों में अंतर को माप कर निवल लेनदार अथवा ऋणी राष्ट्र है या नहीं। यह आंकड़े किसी देश की वित्तीय स्थिति और सुदृढ़ता के संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। निवल आईआईपी, लेनदेन के भुगतान संतुलन के साथ, घरेलू अर्थव्यवस्था के अंतरराष्ट्रीय खातों के समूह को दर्शाता है।

11.49 भारत के लिए, सितंबर 2022 के अंत तक, भारतीय निवासियों की विदेशी वित्तीय संपत्ति 847.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो मार्च 2022 के अंत के स्तर की तुलना में 73.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 7.9 प्रतिशत कम थी, ऐसा मुख्य रूप से आरक्षित परिसंपत्तियों में कमी के कारण हुआ, यद्यपि व्यापार ऋण और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में वृद्धि दर्ज हुई थी। आरक्षित संपत्ति 532.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो भारत की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संपत्ति का लगभग 62.9 प्रतिशत है, जिसमें इसी अवधि में 12.3 प्रतिशत की गिरावट आई है।

11.50 सितंबर 2022 के अंत तक 1,237.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय देनदारियां मार्च 2022 के अंत के स्तर की तुलना में 41.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर (3.2 प्रतिशत) कम थीं। इस गिरावट का मुख्य कारण प्रत्यक्ष निवेश (निवल) बहिर्प्रवाह था, हलांकि अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में मूल्य निर्धारण किया गया तब अन्य मुद्राओं की तुलना में रुपये की विनिमय दर में भिन्नता ने भी देनदारियों में परिवर्तन को प्रभावित किया। सितंबर 2022 के अंत तक कुल विदेशी देनदारियों में ऋण देनदारियों का हिस्सा 50 प्रतिशत था।

11.51 इस प्रकार, भारत पर अनिवासियों का शुद्ध दावा, जिसका मूल्य सितंबर 2022 के अंत तक 389.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, मार्च 2022 के अंत के स्तर से 31.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ गया। सितंबर 2022 के अंत तक भारत की अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संपत्ति, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय देनदारियों का 68.5 प्रतिशत था।

**चित्र XI.18.: सितंबर 2022 के अंत में भारत के शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय निवेश की स्थिति**  
 (क) निवल आईआईपी और जीडीपी के प्रतिशत के रूप में आईआईपी (ख) परिसंपत्ति देयता अनुपात (प्रतिशत में)



स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक; P : अनंतिम

<sup>23</sup> आईएमएफ, भुगतान संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति नियमावली, छठा संस्करण (बीपीएम6) (BPM6),

## सुरक्षित एवमं ठोस वैदेशिक ऋण स्थिति

11.52 सितंबर 2022 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण 610.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो सितंबर 2021 के अंत तक 602.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 1.3 प्रतिशत (यूएस \$ 7.6 बिलियन) बढ़ गया। हालांकि, सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में विदेशी ऋण, सितंबर 2022 के अंत तक एक साल पहले के 20.3 प्रतिशत की तुलना में गिरकर 19.2 प्रतिशत हो गया। शास्त्र दस्तावेज के अनुसार भारत के विदेशी ऋण के लिए इष्टतम सीमा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 23-24 प्रतिशत है।<sup>24</sup> इस प्रकार, जहां तक विदेशी ऋण स्तर का संबंध है, भारत की संभावित वृद्धि सकारात्मक हो गई है। भारत के विदेशी ऋण के विवेकपूर्ण प्रबंधन की गवाही देते हुए, यह कई साथी देशों में, पोस्ट-कोविड के सामने आने वाले विदेशी ऋण संकट के विपरीत है।

11.53 सितंबर 2022 के अंत तक दीर्घकालिक ऋण 478.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो एक साल पहले 498.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, इसी अवधि के दौरान दीर्घकालिक ऋण की हिस्सेदारी 82.8 प्रतिशत से घटकर 78.4 प्रतिशत हो गई। दूसरी ओर, सितंबर 2022 के अंत तक 131.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अल्पकालिक ऋण सितंबर 2021 के अंत तक 104.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। तदनुसार, कुल ऋण में अल्पकालिक ऋण का हिस्सा 17.4 प्रतिशत से बढ़कर 21.6 प्रतिशत हो गया। इस संदर्भ में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि लगभग 97 प्रतिशत अल्पकालिक ऋण आयात के वित्तपोषण के लिए व्यापार ऋण के रूप में है और इसलिए अल्पकालिक ऋण में वृद्धि स्थिरता-अनुकूल है। इसके अलावा, जबकि भारत के विदेशी ऋण का एक बड़ा हिस्सा अमेरिकी डॉलर (सितंबर 2002 के अनुसार 55.5 प्रतिशत) में दर्शाया गया है, भारतीय रुपया-मूल्यवर्गित घटक (30.2 प्रतिशत) विदेशी मुद्रा जोखिम से अलग होकर दूसरी सबसे बड़ा घटक है, जिससे विदेशी ऋण की स्थिरता अनुकूल विशेषताओं में वृद्धि हुई है।

11.54 सितंबर 2022 के अंत तक, सरकारी विदेशी ऋण (एसईडी) की राशि 124.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो एक साल पहले के स्तर से 5.7 प्रतिशत कम है। गैर-सरकारी विदेशी ऋण, सितंबर 2022 के अंत तक 486.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, इसमें एक साल पहले के स्तर से 3.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। डिपाजिट टेकिंग कारपोरेशन (सेंट्रल बैंक को छोड़कर) और नॉन फाइनेंसियल कारपोरेशन गैर-सरकारी ऋण की बड़ी मात्रा के लिए जिम्मेदार हैं।

11.55 **वित्त मंत्रालय का “भारत का विदेशी ऋण:- वित्तीय हैसियत रिपोर्ट 2019-20”**, भारत के विदेशी ऋण के परिवर्तन का विवरण प्रदान करता है।<sup>25</sup> वित्त वर्ष 99 से सरकारी विदेशी ऋण (SED) की तुलना में गैर-सरकारी क्षेत्र के विदेशी ऋण में वृद्धि की प्रत्यक्ष प्रवृत्ति देखी गई है। तदनुसार, आम तौर पर, एक सामान्य वर्ष में, यह गैर-सरकारी विदेशी ऋण में सापेक्ष गति होती है जो देश के विदेशी ऋण में बदलाव लाती है। वित्त वर्ष 21 के महामारी वर्ष में, बहुपक्षीय संस्थानों से कोविड -19 ऋण दिए जाने के कारण यह सरकारी विदेशी ऋण (SED) में वृद्धि थी जो विदेशी ऋण के समग्र विकास के बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार थी। जैसे-जैसे महामारी में कमी आई और अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के साथ सामान्य स्थिति बहाल हुई, मार्च 2022 के अंत में गैर-सरकारी विदेशी ऋण में वृद्धि के रूप में भारत के विदेशी ऋण की सामान्य गति समग्र बाह्य ऋण वृद्धि के 8.0 प्रतिशत में से 4.7 प्रतिशत अंक थी। हालांकि, सितंबर 2022 को समाप्त तिमाही में फिर से सामान्य गति से विचलन देखा गया। यह सरकारी विदेशी ऋण (महामारी वर्ष के समान) में सापेक्ष वृद्धि थी जिसने विदेशी सहायता के साथ-साथ अन्य सरकारी ऋण में गिरावट पर समग्र विदेशी ऋण गति को प्रभावित किया, जिसमें जी-सेक और एसडीआर में एफपीआई निवेश शामिल है। भारत के विदेशी ऋण में 0.4 प्रतिशत की समग्र गिरावट में से, सरकारी विदेशी ऋण (SED) में 0.5 प्रतिशत की गिरावट थी, जबकि गैर-सरकारी (non-SED) में वृद्धि 0.2 प्रतिशत थी।

<sup>24</sup> गोपीनाथ, तुलसी और राजेश्वर एस, तंगजाम (2022): ग्रोथ मैक्सिमाइजिंग एक्सटर्नल डेट ऑफ इंडिया, आरबीआई, बुलेटिन, मई, p 73-86

<sup>25</sup> <https://dea.gov.in/external-debt>; बॉक्स 2.1 देखें

11.56 भारत के विदेशी ऋण भेद्यता संकेतक हानिकारक नहीं बने रहे। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में विदेशी ऋण, सितंबर 2022 के अंत तक 19.2 प्रतिशत था, जो मार्च 2022 के अंत के 19.9 प्रतिशत से कम था। ऋण चुकौती अनुपात (मूल पुनर्भुगतान और ब्याज भुगतान) मार्च 2022 के अंत तक 5.2 प्रतिशत की तुलना में 5.0 प्रतिशत रहा।

11.57 2021 के साथी देशों के साथ भारत के विभिन्न ऋण भेद्यता संकेतकों की तुलना करने से पता चलता है कि सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) के प्रतिशत के रूप में कुल ऋण के अपेक्षाकृत कम स्तर और कुल ऋण के प्रतिशत के रूप में अल्पकालिक ऋण के मामले में देश बेहतर स्थिति में है। विदेशी ऋण के मौजूदा स्टॉक का विदेशी मुद्रा भंडार अच्छी तरह से बचाव कर रहा है।

### तालिका XI.3 विदेशी ऋण बकाया

(अमेरिकी बिलियन डॉलर जब तक कि अन्यथा सूचित न किया गया हो)

क्षेत्र/ इंडस्ट्री/सेक्टर	सितंबर 2021	जून 2022 PR	सितंबर 2022 PR	निरपेक्ष विचलन		प्रतिशत विचलन	
				सितंबर 2021 की तुलना में सितंबर 2022	सितंबर 2022 की तुलना में जून 2022	सितंबर 2021 की तुलना में सितंबर 2022	जून 2022 की तुलना में सितंबर 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
i. सामान्य सरकार	132.0	127.7	124.5	-7.5	-3.2	-5.7	-2.5
ii. सेंट्रल बैंक	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	-18.0	-0.5
iii. सेंट्रल बैंक के सिवाय जमा लेने वाले निगम	160.1	155.3	152.2	-8.0	-3.1	-5.0	-2.0
iv. अन्य क्षेत्र	284.7	301.9	305.6	20.9	3.7	7.3	1.2
iv. 1 अन्य वित्तीय निगम	52.0	51.6	50.5	-1.5	-1.1	-2.8	-2.1
iv. 2 गैर-वित्तीय निगम	232.7	250.3	255.1	22.3	4.8	9.6	1.9
iv. 3 परिवारों को सेवा देने वाले घरेलू और गैर-लाभकारी संस्थान (एनपीआईएसआईएस)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-18.5	-6.3
v. प्रत्यक्ष निवेश: इंटरकंपनी लेंडिंग	26.0	27.7	28.1	2.2	0.4	8.4	1.6
सकल बाह्य ऋण (I से V) (जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)	602.9 (20.3)	612.7 (19.3)	610.5 (19.2)	7.6	-2.3	1.3	-0.4
मेमो आइटम:							
क. कुल दीर्घकालिक ऋण	498.1	486.7	478.7	-19.4	-8.0	-3.9	-1.6
ख. बी. अल्पकालिक ऋण#	104.8	126.1	131.7	27.0	5.7	25.8	4.5

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय

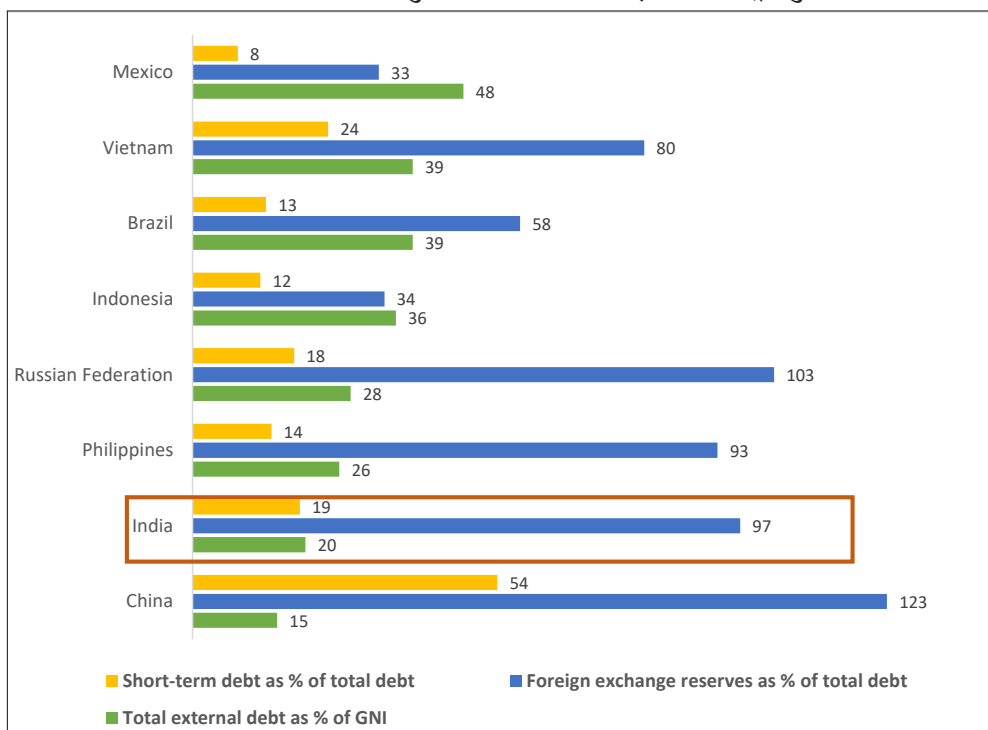
PR: आंशिक रूप से संशोधित; P: अनंतिम

तालिका XI. 4: भारत के प्रमुख विदेशी ऋण संकेतक: स्थिरता का चित्र

प्रतिशत तब तक की अन्यथा सूचित न हो							
मार्च - अंत	विदेशी ऋण( यूएस + बिलियन )	सकल घरेलू उत्पाद और विदेशी ऋण का अनुपात	ऋण चुकोती अनुपात	कुल ऋण और विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात	रियायती ऋण और कुल ऋण का अनुपात	अल्पावधि ऋण ( मूल परिपक्वता ) और विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात	अल्पावधि ऋण ( मूल परिपक्वता ) और कुल ऋण का अनुपात
2017	471.0	19.8	8.3	78.5	9.4	23.8	18.7
2018	529.3	20.1	7.5	80.2	9.1	24.1	19.3
2019	543.1	19.9	6.4	76.0	8.7	26.3	20.0
2020	558.4	20.9	6.5	85.6	8.8	22.4	19.1
2021	573.6	21.2	8.2	100.6	9.0	17.5	17.6
2022PR	619.0	19.9	5.2	98.0	8.3	20.0	19.7
जून अंत 2022 PR	612.7	19.3	4.9	96.5	8.0	21.4	20.6
सितंबर अंत 2022 P	610.5	19.2	5.0	87.3	7.7	24.7	21.6

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय PR: आंशिक रूप से संशोधित; P: अनंतिम

चित्र XI.19: ऋण अनुपात: 2021 के लिए क्रॉस-कंट्री तुलना



स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट, 2022, विश्व बैंक

## सतर्क और आशावान वैदेशिक क्षेत्र की स्थिति

11.58 वैश्विक मांग में कमी भारत के व्यापारिक निर्यात पर दबाव डाल रही है। अनुभवजन्य साहित्य दस्तावेज दर्शाते हैं कि वैश्विक विकास भारत के वास्तविक निर्यात पर एक मजबूत सांख्यिकीय और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है, हालांकि पिछले कुछ वर्षों<sup>26</sup> में इसका प्रभाव कम हुआ है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, (पैरा 11.2), आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार 2022 और 2023 में वैश्विक विकास धीमा होने का अनुमान है। वैश्विक वित्तीय संकट और कोविड-19 महामारी के तीव्र चरण को छोड़कर यह 2001 के बाद से सबसे कम विकास की दर है।

11.59 इस प्रकार, आने वाले वर्ष में निर्यात दर सपाट रह सकती है यदि 2023 में वैश्विक विकास गति नहीं पकड़ता है, जैसा कि कई पूर्वानुमानों से संकेत मिलता है। ऐसे मामलों में, विभिन्न उत्पाद समूह (प्रोडक्ट बास्केट) और गंतव्य विविधीकरण, जिनपर भारत एफटीए के माध्यम से नीति ला रहा है, व्यापार के अवसरों को बढ़ाने के लिए उपयोगी होगा। ऐसे समय में जब वैश्विक विकास और वैश्विक व्यापार जैसा आधार नहीं बढ़ रहा है, निर्यात वृद्धि मुख्य रूप से बाजार हिस्सेदारी लाभ के माध्यम से होगी। यह निर्यात वृद्धि दक्षता, उत्पादकता, प्रौद्योगिकी और नई खोज पर ध्यान देने से होती है। इस स्थिति में सुधार करना होगा। सरकारें मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से बाजारों को खोलने का प्रयास कर सकती हैं। लेकिन, इसका फायदा उठाना निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों के हाथ में है।

11.60 भारत अपने कुछ निर्यात प्रतिस्पर्धी उत्पादों में दक्षिण एशियाई देशों से प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है। घटती कपड़ा क्षेत्र में, बांग्लादेश और वियतनाम हाल के वर्षों में विश्व स्तर पर अपने निर्यात का विस्तार करते देखे गए हैं। इसके अलावा, वियतनाम मशीनरी/उपकरण, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, कुछ कृषि उत्पादों आदि में अपने निर्यात का विस्तार करने में सक्षम रहा है। हालांकि, बड़े पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के लाभ के साथ-साथ कामकाजी आबादी की कम औसत आयु के लाभों को देखते हुए, भारत में लागत प्रभावी तरीके से कई उत्पादों की वैश्विक मांग को पूरा करने की क्षमता है।

11.61 आयात पक्ष पर, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में अनिश्चितता के बावजूद, इसकी कीमतों में हालिया नरमी भारत के पीओएल आयात के लिए अच्छा संकेत देती है। हालांकि, गैर-तेल, गैर-स्वर्ण आयात क्षेत्र, जो विकास के प्रति संवेदनशील हैं, में बड़ी मंदी नहीं आ सकती है, क्योंकि भारतीय विकास लगातार लचीला बना हुआ है।

11.62 संभावित प्रतिकूल घटनाओं को पहचानते हुए, भारत के विदेशी क्षेत्र के लिए आन्तरिक बफर का संज्ञान लेना महत्वपूर्ण है। भारतीय सेवाओं का निर्यात, मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर, व्यापार और यात्रा सेवाओं का योगदान, वर्ष के दौरान अब तक मजबूत बना हुआ है और यह लचीलापन के बड़े पैमाने का प्रतीक है। भारत दुनिया में शीर्ष धन-प्रेषण प्राप्तकर्ता के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है, 2022 के दौरान आवक धन-प्रेषण रिकॉर्ड स्तर पर होने का अनुमान है। तदनुसार, सेवाओं और धन-प्रेषण के तहत एक बड़ा अधिशेष बढ़ते हुए व्यापार घाटे को कम करेगा। वर्षों से चालू खाता घाटे के वित्तपोषण में 'नॉन डेब्ट फ्लो' की बढ़ती हिस्सेदारी को मजबूत करने के लिए, चालू वर्ष के दौरान निवल एफडीआई प्रवाह मजबूत रहा, जबकि हाल के महीनों में निवल एफपीआई प्रवाह सकारात्मक हो गया। इस प्रकार, चालू खाता घाटा (CAD) प्रबंधनीय सीमा के अंदर होगा और स्पष्ट रूप से आर्थिक रूप से प्रबंधनीय रहेगा। इन सबसे ऊपर, विदेशी मुद्रा भंडार दिसंबर

<sup>26</sup> चिनाय, एस. जेड और जैन, टी (2018): व्हाट ड्राइव्स इंडियाज एक्सपोर्ट्स एंड व्हाट एक्सप्लेस द रीसेंट स्लोडाउन? न्यू एविडेंस एंड पालिसी इम्प्लीकेशन; एनसीईआर, पॉलिसी नोट्स; <https://www.ncaer.org/wp-content/uploads/2022/09/a4.pdf>

2022 के अंत तक 562.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर स्थिर रहा, जिसमें 9.3 महीने का आयात शामिल था। भारत के विदेशी ऋण के स्टॉक को विवेकपूर्ण ढंग से प्रबंधित किया गया है।

11.63 एक क्रॉस-कंट्री परिप्रेक्ष्य से भी, भारत के विदेशी क्षेत्र ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है और इसलिए बदलती प्रतिकूल वैश्विक स्थिति का सामना करने के लिए अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में है। जैसा कि भारतीय रुपये द्वारा अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्था (ईएमई) मुद्राओं से बेहतर प्रदर्शन, आरामदायक आयात कवर और मध्यम चालू खाता घाटा से प्रमाणित होता है। भारत के विदेशी ऋण भेद्यता संकेतक अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हानिकारक नहीं हैं। संक्षेप में, जहाँ भारत विदेशी क्षेत्र की चुनौतियों का सामना कर रहा है, वहाँ यह अपने कई साथियों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर निष्पादन कर रहा है, क्योंकि इसमें कठिन परिस्थिति से सफलतापूर्वक निपटने के लिए साधन अन्तर्निहित हैं।